● वर्ष-2
● अंक-256
रायपुर, शनिवार
17 जून 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

नेहरू मेमोरियल अब पीएम मेमोरियल

कांग्रेस ने कहा - नाम में बदलाव प्रतिशोध और संकीर्णता का नतीजा है

नई दिल्ली। दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है। अब नेहरू मेमोरियल को पीएम मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि नाम में बदलाव प्रतिशोध और संकीर्णता का नतीजा है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को अब प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक हुई थी, जिसमें नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के फैसले पर मुहर लग गई।

रक्षा मंत्री और सोसाइटी के उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नाम में परिवर्तन के प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अपने नए रूप में यह संस्थान जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान और उनके सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों से निपटने की उनकी रणनीति को प्रदर्शित करता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री पद को एक संस्था बताते हुए और विभिन्न प्रधानमंत्रियों की यात्रा की तुलना इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों से की। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एक इंद्रधनुष को सुंदर बनाने के लिए उसमें सभी रंगों का आनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। इस प्रकार हमारे सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को सम्मान देने के लिए इस प्रस्ताव के द्वारा इसे नया नाम दिया गया है और यह लोकतांत्रिक भी है।

प्रधानमंत्री मोदी हैं सोसाइटी के अध्यक्ष

जनरल काउंसिल और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष हैं, जबकि राजनाथ सिंह इसके उपाध्यक्ष हैं। इनके अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, वी. मुरली धरण, जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर समेत 29 सदस्य इस सोसाइटी में शामिल हैं। सोसाइटी के कार्यकारी परिषद में आठ सदस्य हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा भी शामिल हैं। सोसाइटी की वित्तीय समिति पांच सदस्यीय है जिसके अध्यक्ष पूर्व राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे हैं।

पीएम मेमोरियल का इतिहास

एडविन लुटियंस की इंपीरियल कैपिटल का हिस्सा रहा तीन मूर्ति भवन अंग्रेजी शासन में भारत के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक आवास था। ब्रिटिश भारत के अंतिम कमांडर इन चीफ के जाने के बाद 1948 में तीन मूर्ति भवन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का आधिकारिक आवास बन गया। पंडित नेहरू 16 साल तक इस घर में रहे और यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद इस तीन मूर्ति भवन को पंडित नेहरू की याद में उन्हें समर्पित कर दिया गया और इसे पंडित नेहरू म्यूजियम एंड मेमोरियल के नाम से जाना जाने लगा। अब केंद्र सरकार ने इसका नाम नेहरू मेमोरियल से बदलकर पीएम म्यूजियम एंड सोसाइटी कर दिया है।

वर्तमान में शोध और अध्ययन का केंद्र है

वर्तमान में यहां व्याख्यान और सेमिनार नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं और विद्वानों के विचार-विमर्श प्रकाशित होते हैं। हरूरू ने हाल के दिनों में अपने शैक्षणिक संसाधनों में काफी विस्तार किया है। आज, पुस्तकालय में न केवल आधुनिक और समकालीन इतिहास का एक संपूर्ण संग्रह है, बल्कि एक प्रभावशाली और विविध अभिलेखीय भंडार भी है। विभिन्न विषयों और रुचि के भारतीय और विदेशी विद्वानों के लिए यह प्रचलित केंद्र है।

कांग्रेस ने फैसले की आलोचना की

कांग्रेस ने केंद्र के इस फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि %नाम में बदलाव प्रतिशोध और संकीर्णता का नतीजा है। बीते 59 सालों से नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी वैश्विक बौद्धिकता का अहम स्थान और किताबों का खजाना रहा है। पीएम मोदी भारतीय राष्ट्र-राज्य के वास्तुकार के नाम और विरासत को विकृत, तिरस्कृत और नष्ट करने के लिए क्या नहीं करेंगे। असुरक्षाओं के बोझ तले दबे एक छोटे कद के व्यक्ति स्वयंभू विश्वगुरु हैं।

उल्लेखनीय है कि साल 2016 में पीएम मोदी ने एक प्रस्ताव रखा था कि तीन मूर्ति परिसर में देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। उसी साल 25 नवंबर को एनएमएमएल की 162वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बीते साल 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री संग्रहालय को जनता के लिए खोल दिया गया था।

कांग्रेस की चिढ़ राजनीतिक अपच का उत्कृष्ट उदाहरण: नड्डा

वहीं, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस यह स्वीकार करने में असमर्थ है कि एक वंश से परे भी नेता हैं। यह राजनीतिक अपच का उत्कृष्ट उदाहरण है। एक के बाद एक ट्वीट में नड्डा ने लिखा, राजनीतिक अपच का उत्कृष्ट उदाहरण-एक साधारण तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थता कि एक वंश से परे ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमारे देश की सेवा और निर्माण किया है। प्रत्येक प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय में सम्मान दिया गया है। नेहरू के सेक्शन को हटाया नहीं गया है बल्कि उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय राजनीति से परे एक प्रयास है, लेकिन कांग्रेस के पास इसे महसूस करने के लिए दृष्टि की कमी है।

नड्डा ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का दृष्टिकोण 'विडंबनापूर्ण' है। क्योंकि पार्टी का एकमात्र योगदान पिछले सभी प्रधानमंत्रियों की विरासत को मिटाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल एक परिवार की विरासत बची रहे। नड्डा ने कहा, भारत पर 50 से अधिक वर्षों तक शासन करने वाली पार्टी के लिए उसकी तुच्छता वास्तव में दुखद है।

इन दिनों

✍ देवेश

भारतीय अमीरों के विदेश जाने का सच

पिछले कुछ सालों से एक वैश्विक ट्रेंड सामने आया है। अचानक से यूरोप या अमेरिका की कोई गैर-सरकारी संस्था अथवा कंसल्टेंसी फर्म एक रिपोर्ट जारी कर देती है। विडम्बना यह है कि हमारे देश की मीडिया इन रिपोर्ट्स पर आंख बंद करके विश्वास कर लेती है और बिना कोई सवाल-जवाब किये उन पर समाचार, लेख और संपादकीय प्रकाशित कर देती है। भारत का मीडिया न इन संस्थानों की पृष्ठभूमि देखता है, न उनके उद्देश्य और रिपोर्ट्स की मेथोडोलॉजी पर कोई क्रॉस चेकिंग की जाती है। अब ऐसे ही हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट कहती है कि भारत में साल 2023 में 6,500 अमीर व्यक्ति देश छोड़कर चले जायेंगे। इससे पहले साल 2022 में 7,500 अमीर भारतीय देश छोड़कर चले गए थे। इस पर कुछ लोग कहेंगे कि अरे देखिये, कितनी बड़ी संख्या में अमीर लोग देश छोड़कर जा रहे है। इसका मतलब देश में राजनैतिक हालत अनुकुल नहीं है और व्यापार की संभावनाएं भी समाप्त हो गयी हैं। यहां अब इन लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। मगर ऐसा नहीं है। वास्तव में यह सभी रिपोर्ट्स शत-प्रतिशत बिजनेस मॉडल होती है। जिसका एक मात्र उद्देश्य पैसा कमाना होता है न कि कोई सामाजिक सरोकार। अब हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की हालिया रिपोर्ट को ही लेते हैं। इसे लंदन की कंसल्टेंसी फर्म हेनली एंड पार्टनर्स ने जारी किया है। इसके अनुसार अमीर लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। यानी वह पहले इसी देश में रहकर अमीर बन चुके थे। इसका मतलब है कि देश के वर्तमान राजनैतिक और आर्थिक परिवेश में लोग अमीर बन रहे हैं। यहां स्थितियां उनके लिए सकारात्मक रही हैं, और अगर यह लोग वास्तव में देश छोड़ रहे है तो इसके दूसरे कारण हैं। जैसे यह लोग अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। या फिर वैश्विक रूप से अपने व्यापार की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। यह भी एक सम्भावना है कि दूसरे देश इन अमीरों को निवेश के एवज में बड़ी छूट देते हों। या फिर इनमें वे अमीर भी शामिल हैं, जो किसी भ्रष्टाचार के मामले से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गये हैं। यह सिर्फ अनुमान नहीं है, बल्कि यह फर्म खुद कहती कि 30 प्रतिशत अमीर इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन प्रोग्राम चुनते हैं। दरअसल, दुनिया के कई देश अपने यहां निवेश आकर्षित करने के लिए गोल्डन वीजा प्रोग्राम चलाते हैं। इस वीजा प्रोग्राम की अपनी एक जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। हर देश चाहता है कि ज्यादा-से-ज्यादा अमीर उनके देश में निवेश करें तो उसके बदले वे उन्हें सभी सुविधाएं देने को तैयार रहते हैं। जैसे ऑस्ट्रिया का गोल्डन वीजा लेने पर यूरोपियन यूनियन की नागरिकता मिलने का मौका मिल जाता है। नार्थ मैसिडोनिया में निवेश कीजिये और हांगकांग, जापान, सिंगापुर और यूरोप के कुछ हिस्सों में आने-जाने पर कोई रोकटोक नहीं होगी। हेनली एंड पार्टनर्स की वेबसाइट के अनुसार यह सभी देश इसके क्लाइंट हैं। यानी यह कंपनी भारत सहित दुनियाभर के अमीरों से संपर्क करती है। उन्हें इन देशों द्वारा गोल्डन वीजा के अंतर्गत मिलने वाले फायदों का लालच दिखाती है। एकबार कोई अमीर क्लाइंट उनके प्रभाव में आता है तो उससे यह पैसा बनाते हैं।

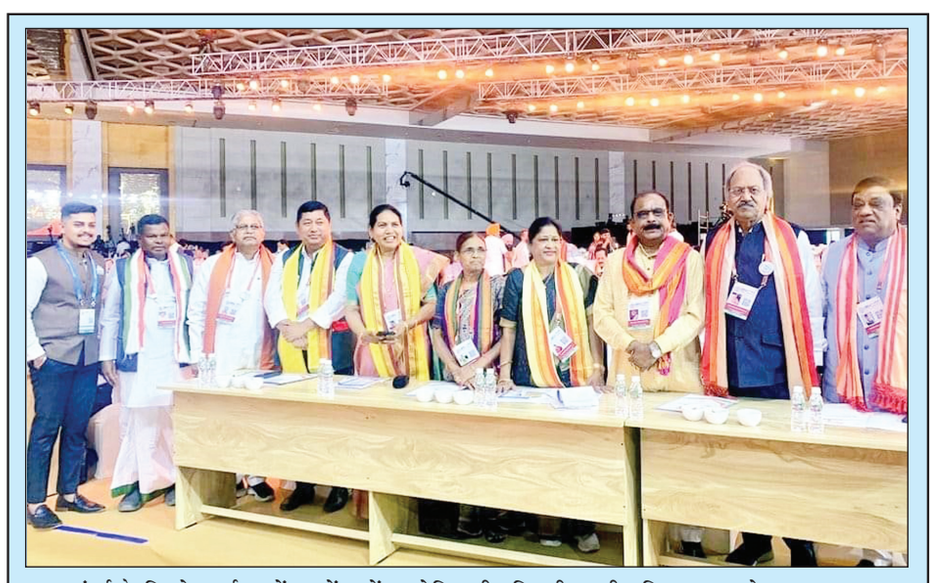

मुंबई के जिओ वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 के शुभारंभ समारोह शामिल छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन देश भर के विधायकों के लिए एक मंच पर एक साथ आने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा।

इंफाल में केंद्रीय मंत्री के घर को लगाई आग

इंफाल। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा की ताजा घटना में केंद्रीय मंत्री के घर में आग लगा दी गई। मणिपुर सरकार की ओर से बताया गया कि भीड़ ने गुरुवार देर रात केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के कोंगबा स्थित आवास में आग लगा दी। गनीमत रही कि केंद्रीय मंत्री घटना के समय घर पर नहीं थे। इससे पहले कुछ उपद्रवियों ने बुधवार को इंफाल पश्चिम के लाम्फेल क्षेत्र में एक मंत्री के घर को आग लगा दी थी। नेमचा किपगेन भाजपा और राज्य सरकार में मंत्री हैं। किपजेन 2017 से कांगपोकपी निर्वाचन क्षेत्र से मणिपुर विधानसभा की सदस्य हैं।

इंफाल शहर के बीचोंबीच गुरुवार दोपहर दो घरों को जलाए जाने और मणिपुर त्वरित प्रतिक्रिया बल (रैपिड एक्शन फोर्स ऑफ मणिपुर) और भीड़ के बीच झड़पों के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार देर रात शहर में घूमने वाली भीड़ की सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी हुई।

मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने अपने बयान में क्या कहा?

विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि मैं इस समय आधिकारिक काम के लिए केरल में हूं। शुक्र है कि कल रात मेरे इंफाल स्थित घर में कोई घायल नहीं हुआ। बदमाश पेट्रोल बम लेकर आए थे। मेरे घर के भूतल और पहली मंजिल को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे गृह राज्य में जो हो रहा है उसे देखकर बहुत दुख होता है। मैं अब भी शांति की अपील करता रहूंगा। इस तरह की हिंसा में लिप्त लोग बिल्कुल अमानवीय हैं।

उन्होंने कहा, मैं कोच्चि में हूं और अपने राज्य (मणिपुर) में नहीं हूं। मैंने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया था। मेरे घर पर हमला होने पर मुझे दुख है और अपने राज्य के नागरिकों द्वारा ऐसे रवैये की अपेक्षा नहीं की थी। राजकुमार रंजन सिंह आगे कहा, मुझे बताया गया कि घर में आग लगी थी लेकिन लोगों ने दमकल की गाड़ी वहां तक पहुंचने नहीं दी। ऐसा लगता है जैसे यह मेरे जीवन पर हमला है। यह दिखाता है कि मणिपुर में कानून-व्यवस्था खत्म हो चुकी है और मौजूदा सरकार शांति व्यवस्था बनाने में विफल रही है। मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बता दिया है।

गोदाम में लगाई आग

शुक्रवार की शाम को उपद्रवियों ने इंफाल पैलेस मैदान के पास एक वेयरहाउस में आग लगा दी। फायर ब्रिगेड और सुरक्षा बलों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और उपद्रवियों को भगाया। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और उपद्रवियों के बीच झड़पें भी हुईं। वेयरहाउस आदिवासी समुदाय के एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी का है।

प्रमुख समाचार

भाजपा को हराने के लिए पवार का ने तैयार की फॉर्मूला

नई दिल्ली। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर एकता बनाने की जरूरत है। महाराष्ट्र के जलगांव में संवाददाताओं से बात करते हुए विपक्ष के दिग्गज नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उन अधिकांश राज्यों में खारिज कर दिया गया था जहां वह शासन कर रही थी, उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए निर्वाचित सरकारों को गिरा दिया था। राकांपा प्रमुख ने कहा, अगर लोगों ने राज्य स्तर पर भाजपा को खारिज कर दिया है तो राष्ट्रीय स्तर पर उनका नजरिया अलग नहीं होगा। बिहार के पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में अपना विचार रखने की जानकारी देते हुए पवार ने कहा, सभी गैर-भाजपा दलों को एक साथ बैठने और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर विपक्षी एकता बनाने के बारे में सोचने की जरूरत है।

कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में खिला कमल

भोपाल। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति दिलचस्प मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव से कुछ महीने पहले भाजपा को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कमल खिला है। भाजपा इसे शुभ संकेत बता रही है और साथ ही साथ कह रही है कि चुनाव की शुरुआत जीत से हुई है। छिंदवाड़ा में पार्टी के लिए जीत कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को नया हौसला देगा तो वहीं कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। उप चुनाव के परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए। राज्य चुनाव कार्यालय द्वारा घोषित परिणामों के अनुसार पार्षदों के पद के लिए कुल 13 स्थानीय निकाय उपचुनाव हुए थे, जिनमें से सात पर भाजपा ने और छह पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है।

ईडी ने कैश फॉर जॉब घोटाले में सेंथिल के भाई को समन

चेन्नई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कथित कैश-फॉर-जॉब घोटाले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के भाई अशोक कुमार को समन जारी किया। वित्तीय जांच एजेंसी के अनुसार, अशोक कुमार अपराध की आय के लाभार्थी है। सूत्रों के मुताबिक, कई शिकायतकर्ताओं ने पहले अशोक कुमार पर नौकरी देने के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि, आरोपी मंत्री को खराब स्वास्थ्य के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जिसके कुछ घंटों बाद अदालत ने उन्हें 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आयकर विभाग ने भी पिछले महीने तमिलनाडु के मंत्री से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी।

स्कूल में प्रार्थना के समय बजा अजान, जांच के आदेश

मुंबई। मुंबई के कांदिवली पश्चिम के एक निजी स्कूल में अज़ान बजने से बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। मामला प्रकाश में आने के साथ ही जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता भी पूरे मामले को लेकर आक्रमक हो गए हैं। भाजपा नेताओं की मांग है कि पूरे मामले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। स्कूल के बाहर हंगामें को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। पुलिस उपायुक्त एके बंसल ने कहा कि विरोध और शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शिकायत का संज्ञान लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इसकी सभी कोणों से पूछताछ की जाएगी और सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भाजपा मुंबई के महासचिव और स्थानीय विधायक योगेश सागर ने स्कूल के बाहर एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया और मांग की कि जब तक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती ह।

जेके गजनवी फोर्स के आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर

श्रीनगर। संयुक्त सुरक्षा बलों ने आज सुबह जेके गजनवी फोर्स के पांच उच्च प्रशिक्षित विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया। अफगान-पाक थिएटर में छापामार युद्ध में अनुभवी आतंकवादी, कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास जुमागुंड क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। पांच आतंकवादियों के समूह की संभावित घुसपैठ के बारे में कुपवाड़ा पुलिस द्वारा विकसित विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, जुमागुंड क्षेत्र में घुसपैठ के संभावित मार्ग पर सेना के साथ ऑपरेशन की योजना बनाई गई थी और उसी के अनुसार घात लगाकर हमला किया गया था। जेकेजीएफ से संबंधित समूह में जम्मू-कश्मीर में पुंछ जिले के निवासी रफीक नाई और शमशेर नाई उर्फ जफर इकबाल हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में हैंडलर के रूप में काम करता था और मुर्तजा पठान उर्फ गजनवी, पाकिस्तान में फैसलाबाद का निवासी हैं। पीओजेके से सामरिक पहलू की निगरानी करने वाले ऑपरेशनल कमांडर के रूप में देवबंद स्कूल ऑफ थिंक से संबद्ध है।

इतिहास से कैसे सीख सकता है विपक्ष

केसी त्यागी

विपक्षी एकता की पहले भी कई कोशिशें हो चुकी हैं। 80 के दशक की एक घटना ऐसी जुगत में लगे नेताओं के लिए आईना भी है और सबक भी। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बाद सबसे बड़े दल के नेता के रूप में चौधरी चरण सिंह उभरे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में उन्हें मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी मिला हुआ था। देश के लगभग सभी राज्यों में उनकी मौजूदगी थी, लेकिन पार्टी के आंतरिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी बीच जुलाई 1982 में राजधानी से प्रकाशित एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार की एक खबर ने सनसनी फैला दी।

खबर यह थी कि हरियाणा के नेता चौधरी देवीलाल की इंदिरा गांधी से लंबी मुलाकात हुई है और भविष्य में भी साथ काम करने की संभावना बन रही है। चरण सिंह को जब इस खबर का पता चला तो उन्होंने तुरंत देवीलाल को दल से निकाल दिया। आम तौर पर नोटिस देकर जवाब मांगने की प्रक्रिया भी इस मामले में किनारे कर दी गई। हालांकि कुछ घंटों के अंदर ही देवीलाल का स्पष्टीकरण भी प्रेस को जारी किया गया कि वह चरण सिंह को अपना नेता मानते हुए इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध चल रहे अभियानों में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते रहेंगे। लेकिन कड़वाहट इस कदर थी कि कोई बीच-बचाव का रास्ता नहीं था। पार्टी में बवंडर का आलम यह था कि बीजू पटनायक, कर्पूरी ठाकुर, कुंभाराम आर्य, मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस, रवि राय, राम विलास पासवान, शरद यादव आदि सभी नेताओं ने

देवीलाल के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी और दल के विभाजन का खाका तैयार हो गया। 9 अगस्त 1982 को विश्व युवक केंद्र में एक सम्मेलन आयोजित कर नए दल का नामकरण ङ्क लोकदल (क) कर दिया गया, अध्यक्ष कर्पूरी ठाकुर चुने गए। राज्य स्तर पर दल के कार्यक्रम आयोजित होते रहे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह दल कोई छाप छोड़ने में असफल रहा।

तब भी भारत 'जोड़ो' यात्रा

इस बीच जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर का प्रोग्राम तय हो चुका था कि वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा कर जनता के ज्वलंत मुद्दों पर जन-जागरण कर पार्टी में नई जान फूंकने का प्रयास करेंगे। उनकी पदयात्रा 3 जनवरी 1983 से कन्याकुमारी से शुरू हुई, जहां जनता पार्टी के विधायक आर के राघवन ने बड़ी भूमिका निभाई। यहां बताना जरूरी है कि जनता पार्टी के विभाजन के बाद दक्षिण भारत के अधिकांश नेता मूल दल के साथ ही बने रहे और पदयात्रा में इसका एहसास भी हुआ। पदयात्रा शुरू होने के तुरंत बाद कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने लगे। वहां जनता पार्टी पूर्ण बहुमत पाने में कामयाब रही। तब कर्नाटक जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में एचडी देवेगौड़ा, एसआर बोम्मई, जेएच पटेल और रामकृष्ण हेगड़े थे। इन सबको क्रमशः कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिला। चंद्रशेखर का विश्वासपात्र होने के कारण हेगड़े मुख्यमंत्री चुने गए। सुधींद्र भदौरिया पद यात्रा के मुख्य संचालकों में थे। लोकदल (क) राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में असफल रहा, इसलिए 27 जनवरी को आनन-फानन इसका जनता पार्टी में विलय कर दिया गया। फरवरी में पदयात्रा बेंगलुरु पहुंची और वहां जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई।

लोकदल (क) के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी आमंत्रित था, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, देवीलाल, बीजू पटनायक, जॉर्ज फर्नांडिस, रवि राय, कुंभाराम आर्य के साथ युवा पदाधिकारी के नाते मैं भी शामिल रहा। समूचे बेंगलुरु में चंद्रशेखर और हेगड़े के कटआउट छाए हुए थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले सभी नेताओं का परिचय हुआ, लेकिन हरियाणा और बिहार जनता पार्टी के मूल नेताओं की धमाकेदार उपस्थिति ने देवीलाल और कर्पूरी ठाकुर के माथे की सिलवटें बढ़ा दीं। जनता पार्टी के कार्यकाल में हरियाणा में देवीलाल के मुखर विरोधी सुषमा स्वराज, का. शंकरलाल, बलदेव तायल पहली पंक्ति में बैठे थे। उन्हें देखकर चौधरी देवीलाल के चेहरे पर लकीरें भविष्य के संकेतों को साफ उजागर कर रही थीं। मोरारजी भाई और चंद्रशेखर समर्थक नेता रोज उनके विरुद्ध बयानबाजी करते थे। लिहाजा जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के परिणाम भविष्य की अनहोनी के स्पष्ट संकेत दे रहे थे।

मोदी सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पितः रंजना

■ गरियाबंद जिले के गोहरापदर में आयोजित विशाल जनसंवाद कार्यक्रम में धमतरी विधायक शामिल हुई

धमतरी। गरियाबंद जिला के गोहरापदर में विशाल जनसंवाद कार्यक्रम में भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां गिनाई, जहां पर महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के संचालक प्रभारी पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान कुरूद विधायक अजय चंद्राकर के नेतृत्व में लगातार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, इसी तारतम्य में बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोहरापदर में विशाल जन संवाद सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सह प्रभारी पूर्व सांसद चन्दूलाल साहू, पूर्व कैबिनेट मंत्री व पूर्व सांसद चंद्रशेखर साहू, सांसद चुन्नीलाल साहू, बिंद्रानवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी, धमतरी विधायक रंजना साहू, गरियाबंद भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश साहू सहित अनेक वक्ताओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को जनसंवाद के माध्यम से जनता के समक्ष रखें और छत्तीसगढ़ प्रदेश को भ्रष्टाचार की दलदल में फंसाने वाले भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता को बताएं। जिसमें विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने कहा जनहित के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने अनेक

योजनाएं संचालित किए, जिसका लाभ विगत 9 वर्षों से जनता को मिल रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा है, उन्होंने उज्जवला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, धान सहित विभिन्न खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य में वृद्धि, हर घर नल जल योजना से जल पहुंचाना, किसानों को सलाना सम्मान निधि आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज, महिला सशक्तिकरण के लिए घर घर में शौचालय निर्माण कोरोना काल से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से मुफ्त राशन , करोड़ों भारतवासियों का स्वयं का जनधन खाता जैसे अनेक योजनाएं जनता के लिए लाई जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बेमिसाल जनता की सेवा, देशवासियों के स्वाभिमान के लिए सुशासन का निर्माण और गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं के द्वारा कल्याणकारी कार्यों का संचालन ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है।विधायक रंजना साहू ने भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार लोलुपत हो चुका है, और पूरे छत्तीसगढ़ को कर्ज के दलदल में डाल दिए, कांग्रेस की सरकार घोटाले बाजों की सरकार हैं, जो जनता के हितों को रोककर शासन के पैसे का दुरुपयोग करती है और अपनी जेबें भर रही है। शराबबंदी की घोषणा कर महिलाओं के साथ छलावा करने वाली कांग्रेस की सरकार हैं, कांग्रेस सरकार ने जनता को लूट कर अपनी जेब भरा और नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के नाम पर केंद्र सरकार के 15 वें वित्त के पैसे का दुरुपयोग करते रहे, केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना को रोककर गरीबों के पक्के छत के सपने को चकनाचूर करने वाली भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार है, प्रत्येक घर नल जल पहुंचाने की महकती योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया, ऐसे अनगिनत जनहित कार्यों को रोककर छत्तीसगढ़ प्रदेश को कर्ज के दलदल में डालने वाली कांग्रेस की सरकार है।

अभिवादन व स्नेह ही हमारी कुंजी है : विधायक

■ गौ माता के चरणरज से निकले धूल नवविवाहितों के लिए आशीर्वाद है : सांसद चुनीलाल

धमतरी। धमतरी शहर से लगे ग्राम शंकरदाह में मुख्य अतिथि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय चुन्नीलाल साहू अध्यक्षता विधायक रंजना डीपेंद्र साहू सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में साहू समाज भवन में शेड निर्माण, किचन शेड निर्माण, बोर खनन नल टंकी फिटिंग, आंगनवाड़ी, निर्माण हाई स्कूल प्रांगण पर कला मंच निर्माण, हायर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण पर सांस्कृतिक कला मंच निर्माण सहित विभिन्न कार्यों का लोकार्पण संपन्न हुआ।

सांसद एवं विधायक के आगमन पर बाजे गाजे के साथ स्वागत किया गया। सर्वप्रथम साहू समाज की आराध्य देवी भक्त माता कर्मा की पूजा अर्चना समस्त अतिथियों ने की। मंच में विराजमान अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर बेच लगाकर सम्मान ग्राम वासियों के द्वारा किया गया। सांसद माननीय चुन्नीलाल साहू ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में समाज में जागरूकता लाने की अति आवश्यकता है, और इसके लिए समाज के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए समाज को आगे बढ़ाएं आज की परिस्थिति का वर्णन करते हुए सांसद जी ने आगे कहा कि गोधूलि बेला में विवाह करना सर्वाधिक शुभ माना गया है, क्योंकि गौमाता के चरण रज से निकले हुए धूल नवविवाहित के लिए आशीर्वाद है, इसलिए हमारी पुरानी परंपरा को पुनः आज के परिवेश में लाने की आवश्यकता है। भक्त माता कर्मा जो त्याग तपस्या की देवी है उन्होंने मातृ सम्मान के लिए कार्य किए और आज मातृशक्तियों को आगे बढ़कर समाज के विकास में अपना योगदान देना होगा। आतिथ्य उद्बोधन में विधायक रंजना साहू ने कहा कि माताओं के सम्मान के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घर घर में शौचालय निर्माण करा कर हमें सम्मान से आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाएं, छत्तीसगढ़ में धमतरी पहला जिला रहा है जो शौच मुक्त हुआ, इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक योजनाएं माताओं के सम्मान के लिए उनके स्वास्थ्य के लिए लाए हैं। सामाजिक विषयों पर विचार प्रगट करते हुए विधायक ने कहा कि व्यवहारिक जीवन में मां कर्मा के उपदेश को अपनाना अति आवश्यक है विवाह में साड़ी देने की परंपरा को खत्म करना होगा, और हमें स्वयं स्वीकार करना होगा कि अभिवादन और स्नेह ही हमारी पूंजी है जो सदैव हमारे रिश्ते को प्रेम की डोरी से बांध कर रखेंगे। इस अवसर जिला पंचायत सदस्य कविता बाबर, जनपद अध्यक्ष मनीषा साहू, भोथली मंडल अध्यक्ष हेमंत चंद्राकर, सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू, पूर्व जिला साहू संघ महासचिव विजय साहू, पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रियंका राजीव सिन्हा, साहू समाज परिक्षेत्र अध्यक्ष हंसराज साहू, सरपंच नरेंद्र साहू, उपसरपंच सोमन साहू, डोड़की सरपंच प्रदीप सिन्हा, शंकर लाल साहू आदि उपस्थित थे।

सक्ती में किया गया वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान

सक्ती। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की सफ्लतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष जनसंपर्क का कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय सक्ती के सक्ती विधानसभा क्षेत्र का विधानसभा स्तरीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन एवं सम्मान समारोह भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय सक्ती में किया गया। कार्यक्रम को

संबोधित करते हुए सक्ती विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री डॉ खिलावन साहू ने इस आयोजन के उद्देश्य प्रकाश डालते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सफ्लतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान है आप लोगों की परिश्रम से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने में सफ्ल रहा है जिसमें प्रमुख रुप से प्रधानमंत्री जनधन योजना ,भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 व 35ए, तीन तलाक बिल,देश के 80 करोड़ हितग्राहियों को फ्री में चावल, ढाई करोड़ से अधिक आवासहीनो को प्रधानमंत्री आवास ,प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर, मुद्रा योजना बहुत सारे विकास के भी कार्य को डॉ साहू ने गिनाया। कार्यक्रम प्रभारी रामावतार अग्रवाल एवं सह प्रभारी श्री रमेश सिंघानिया ने भी संबोधित करते हुए कहा कि यह पार्टी नहीं परिवार है इसलिए हम इस प्रकार के मिलन का कार्यक्रम टिफ्फिन भोज और सम्मान का कार्यक्रम कर रहे हैं सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को गमछा, कमल फूल एवं गुलाब फूल से सम्मानित किया गया वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी अपने पुराने अनुभव सुनाए।

मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ कार्यकर्ता विवेकी गवेल,पूरी राम सूर्यवंशी थे। कार्यक्रम मे पंडित नारायण शर्मा,जवाहर जयसवाल,घाँसी राम बंसल , कमलेश शर्मा, प्रीतम सिंह गवेल ,ओम प्रकाश अग्रवाल, गुलाब खेतान,दीन दयाल राठौर, बहोरन साहू, चंदमणि बैस,ध्यान दास गबेल, लखन चंद्रा,समारु राम यादव, परमेश्वर गौरहा नंदकिशोर तंबोली ,विश्वनाथ शंकर राठौर, नीलकंठ राठौर, कृष्णा कसेर, बिसाहू दास महंत ,बालेश्वर वैष्णव, विनोद अग्रवाल,बुधवार सिंह यादव, गांधी राम जयसवाल ,बिसाहू श्रीवास ,रथ राम श्रीवास, धरम रात्रे, नरोत्तम साहू ,दुरूप साय गवेल, विजय राठौर, पोखर जयसवाल, मोहन तोदी, महावीर राठौर, कपूरचंद अग्रवाल, प्रेम लाल राठौर ,चेक राम साहू ,मोहन यादव, सुखदेव उरांव, दामोदर बरेठ, अर्जुन सोनी , मंडल अध्यक्ष गण अनूप अग्रवाल, संतोष राठौर, प्रेम पटेल ,प्रभात सिंह, राम नरेश यादव दीपक गुप्ता दीपक ठाकुर धनंजय नामदेव के के देवांगन हेतराम देवांगन, आदित्य अग्रवाल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन चितरंजन पटेल एवं अमन डालमिया ने किया आभार नगर मंडल अध्यक्ष अनूप अग्रवाल ने किया।

राजीव गांधी देश में संचार क्रांति लाए भाजपा ने उपयोग कर हासिल की सत्ता

दुर्ग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी संचार क्रांति लेकर आए। भाजपा ने 2014 के चुनाव में मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। इसके माध्यम से गलत प्रचार-प्रसार कर केंद्र की सत्ता हासिल कर ली, पर कांग्रेस इस तकनीकी का उपयोग नहीं कर पाई।

सोशल मीडिया से जुड़ना होगा

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि, अब 2023 के चुनाव में सोशल मीडिया के माध्यम से इतिहास में कांग्रेस नेताओं का योगदान, उनकी जनकल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाना है। केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़ना है। सीएम बघेल शुक्रवार को कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में बोल रहे थे।

टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए प्रशिक्षण शिविर

दुर्ग के पाटन में हो रहे कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि, जोन और सेक्टर स्तर के कार्यकताओं को सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की ताकत समझाने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर विशेष रूप से कार्यकर्ताओ को एक्टिव रहने की बात कही।

कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि, वर्तमान में प्रदेश में 70 लाख लोग फेसबुक और व्हाट्स ऐप का उपयोग कर रहे है। वहीं 40 लाख लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण टिप्स दिए और सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाए जाने की बात कही। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

पोलसायपारा तालाब का काम 15 दिन में शुरू नहीं हुआ तो प्रदर्शन

■ क्षेत्रवासियों के साथ मिल कर युवा मोर्चा निगम में करेगा प्रदर्शनः नितेश

दुर्ग। पोलसाय पारा तलाब जोकि शहर के बीचो बीच स्थिति है, जिसकी दायनीय स्तिथि को लेकर युवा मोर्चा प्रदेश सह कोषाध्यक्ष नितेश साहू ने निगम प्रशासन व महापौर पर अनदेखी का पर आरोप लगाते हुए दुर्ग निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंप आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा की पोलसाय पारा तलाब आज निगम की उदासीनता के कारण बद से बदतर स्थिति में है तलाब जलकुंभी उसे पटा हुआ है, और तालाब के चारों ओर सिर्फ गंदगी का आलम है, तलाब के पानी से अब बदबू भी आना शुरू हो गया है, जिससे महामारी फैलाने का भी खतरा है इस विषय को लेकर युवा मोर्चा ने पहले भी महापौर को अवगत कराया जा चुका है, पर तलाब की स्तिथि और बुरी हो गई पर महापौर को आम जन की तकलीफ़ से कोई मतलब नहीं है यही हाल दुर्ग

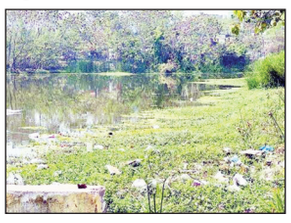

विधायक अरुण वोरा का है लगातार यहाँ से गुजरने के बाद भी इस तालाब की स्तिथी को नहीं देख पा रहे है पूरे दुर्ग के तलाबों की स्तिथि यहीं है, और जल्द ही मानसून भी आने वाला है, फ्रि मानसून का बहाना लेकर निगम टाल मटोल करेगी युवाओ ने 15 दिन में साफ सफ़ाई नहीं होने की स्तिथि में आंदोलन कर निगम के घेराव की चेतावनी दी हैं ज्ञापन सौंपने वालो में प्रमुख रूप से नितेश साहू, चंद्रकांत साहू, लवकुश ताम्रकार, सुधीर बोयर, पीयूष मालवीय, सुधाकर बनवासी, मंगल राजपूत, देवेंद्र टंडन, पप्पू यादव, पप्पू देवांगन, निरंजन दुबे, समीर कौशल, मिंकु तम्रकार, शुभम कोंबे, विक्की सोनी, कमल सूर्या, अजय साहू, सोनू ख़ान आदि उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

दुगली क्षेत्र के किसान खाद बीज के लिए भटक रहे

नगरी। मानसून आने के पहले दुगली क्षेत्र के ग्रामीण किसानों को बार-बार सोसाइटी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि उन्हें खाद नहीं मिल रहा है जबकि खाद के लिए कई बार यहां आकर चक्कर काट रहे हैं। मयाराम नागवंशी, महेन्द्र नेताम, रामलाल तुमरेटी, मानसाय मरकाम, बंशीलाल सोरी, रोहित कोमरे व बालमुकुन्द नेताम ने बताया कि सोमवार मंगलवार बुधवार को डोंगरडूला स्थित सोसाइटी पर खाद लेने के लिए किसानों को भीड़ जमा थी, अन्य क्षेत्रों के किसान खाद लेने पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है निराश होकर लौटना पड़ रहा है। किसानों की जरूरत का खाद सोसाइटी में उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार बड़ी-बड़ी बातें करते हैं मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके प्रशासन गांव में जाकर देखें कि वहां की जमीनी हकीकत क्या है, वहां के हालात कैसे हैं, किसान कितने परेशान हैं, आषाढ़ का सीजन लग चुका है और सरकारी समिति के कर्मचारियों को सरकार की मिलीभगत से उन्हें हड़ताल में भी बिठा दिया गया है ताकि जानबूझकर खाद की किल्लत हो और किसान परेशानी में पड़े रहे।

नोटिस के बाद भी नही हटे तो निगम ने जेसीबी से हटाया

दुर्ग। नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत वार्ड 10 शंकर नगर सरस्वती विद्यापीठ के पीछे, नाला के पास कब्जाधारी लालू राठौर द्वारा स्वयं के भवन के पास सड़क क्षेत्र में अस्थाई फेंसिंग कर बाड़ी बनाकर अतिक्रमण किया गया है, जिससे आवाजाही में मार्ग बाधित हो रही थी एवम लोगो को परेशानियो का सामना करना पड़ता था, शिकायत के आधार पर उक्त फेंसिंग को आवाजाही मार्ग से हटाये जाने के लिए अनावेदक को इस कार्यालय से नोटिस प्रेषित की गई थी. अतिक्रमणकर्ता द्वारा आज दिनांक तक फेंसिंग को आवाजाही मार्ग से हटाया नहीं गया और जवाब भी संतोषप्रद नही रहा। सड़क क्षेत्रअंतर्गत में अतिक्रमण-अवैध कब्जा पाया गया है। जिसको आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश पर सहायक भवन अधिकारी गिरीश दीवान के नेतृत्व एवं अतिक्रमण अधिकारी नोडल दुर्गेश गुप्ता के साथ वार्ड 10 शंकर नगर, सरस्वती विद्यापीठ के पीछे से लालू राठौर द्वारा किये गये अतिक्रमण / अवैध कब्जा को जेसीबी की मदद से हटाकर कब्जा मुक्त किया गया।

महिला कांग्रेस ने फूंका बृजभूषण शरण का पुतला

गरियाबंद। महिला यौन उत्पीड़न आरोपों से घिरे भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की गई. तहसील मुख्यालय मैनपुर नगर में दोपहर 1 बजे ब्लॉक महिला कांग्रेस मैनपुर ने केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. बस स्टैण्ड थाना के सामने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण की रावण रूपी विशाल पुतले का दहन किया। इस दौरान जिला पंचायत गरियाबंद के उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी रहे संजय नेताम ने कहा कि भाजपा के सरकार में देश के भीतर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के उपर महिला पहलवानों के द्वारा आरोप लगाने के बाद भी अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होना समझ से परे है। केन्द्र की भाजपा सरकार यौन उत्पीड़न के आरोप में घिरे भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह को बचाने में लगी हुई है और उन्हें पूरा संरक्षण दिया जा रहा है.मैनपुर ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका कपिल ने कहा कि लोकतंत्र के साथ देश मे खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के लिए मैडल लाने वाली बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।

डॉ. रमन सिंह से मिला धीवर समाज का प्रतिनिधिमंडल

धमतरी। शरीर सौष्ठव के खेल में लगातार 32 वर्षों से साधनार धीवर समाज और धमतरी नगर का नाम रोशन करने वाले रमेश हिरवानी को एशिया महाद्वीप में बॉडी बिल्डिंग खेल में 22 अक्टूबर 1994 से 26 फरवरी 2023 तक सबसे अधिक 24 बार व्यक्तिगत टाइटल जीतने के लिए 5 जून 2023 को गोल्डन बुक ऑफवर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि रमेश हिरवानी ने यह उपलब्धियां बिना कोई सप्लीमेंट्री लिए छत्तीसगढ़ में उपलब्ध सामान्य भोजन सब्जियां ग्रहण करके प्राप्त किया। उन्होंने सिद्ध किया कि छत्तीसगढ़ की हवा पानी, माटी और अन्न में इतनी शक्ति है कि दूसरा कोई शक्तिवर्धक सप्लीमेंट्री लेने की आवश्यकता ही नहीं है। रमेश हिरवानी की वर्ष 1989 से 2023 तक प्राप्त पदों की बहुत लंबी फेहरिस्त है। संक्षेप में वह 2 बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता थाईलैंड एवं इंडोनेशिया में भाग लिया। 11 बार सीनियर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जबलपुर, जालंधर, चंडीगढ़, भिलाई, भुवनेश्वर, कुच बिहार, हैदराबाद में खेले।

हड़ताली समितियों पर कार्रवाई हुई प्रारंभ

बलौदाबाजार। शासन प्राप्त निर्देश के अनुरूप कलेक्टर चंदन कुमार ने आज शासकीय उचित मूल्य दुकानों की संचालन करने वाली कुल 18 हड़ताली सेवा सहकारी समितियों की आईडी को निलंबित कर आसपास के राशन दुकानों में संलग्नीकरण किया गया है। इस हेतु जिले के विभिन्न एसडीएम ने आदेश जारी किया है। जिसके तहत कसडोल अनुविभाग के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकान कसडोल-2, सेमरिया, कोट क, सर्वा, मल्दा, ठाकुरदिया, अर्जुनी ब, असनींद को निलंबित किया गया है। इसी तरह भाटापारा अनुविभाग अंतर्गत हथनीपारा, गांधी मंदिर, महासती वार्ड, दतरेंगी, राजाढार, मोपका, भोथीडीह, गाड़ाडीह एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड शामिल है। राशनकार्डधारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इनका संलग्नीकरण इस प्रकार किया गया है। कसडोल-2 का कसडोल आईडी क्रमांक-52101304 में, सेमरिया को ग्राम टेमरी में, कोट क को छांछी में, सर्वा को ग्राम भदरा में, मल्दा को मुड़पार म में शामिल किया गया है।

सामाजिक माहौल खराब करने वालों पर करें कार्यवाही : गृहमंत्री

■ गृहमंत्री साहू ने क्राइम और कानून व्यवस्था पर ली समीक्षा बैठक

■ अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के दिए निर्देश

बेमेतरा। प्रदेश के लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास, धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज बुधवार को बेमेतरा प्रवास के दौरान जिला कार्यालय कलेक्टोरेट के दिशा-सभाकक्ष में गृह विभाग के अधिकारियों की क्राइम एवं कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता से जिले के थाना, परिसीमन, चौकी, लाइन, बल की उपलब्धता तथा सुरक्षा संबंधित अन्य

विषयों की जानकारी ली। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने जिले में चल रहे कानून व्यवस्था और घटनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। गृह मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को सीमा क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखते हुए जिले के आंतरिक क्षेत्रों में भी निगरानी रखे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक को जिले में सुरक्षा बल की और आवश्यकता होने पर जानकारी भेजने को कहा। उन्होंने जिले में आक्रामक भाषण और सामाजिक माहौल खराब करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को कहा एवं जिले में साइबर केस के संबंध में जानकारी ली और साइबर क्राइम के थानों पर अत्याधुनिक उपकरण की व्यवस्था करने को कहा एवं महिला अपराध जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। गृहमंत्री ने बताया कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिले में होने वाली क्राईम गतिविधियों पर अभी से अंकुश लगाना प्रारंभ कर दो। इसके अलावा अवैध रूप से शराब की बिक्री करने वालों पर लगातार निरीक्षण कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

गृहमंत्री साहू ने महिलओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा और जिले में हुक्का, नशीले पदार्थों पर लगातार मॉनिटरिंग करते हुए प्रभावकारी कदम उठाने के निर्देश दिए। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कहा कि इन सब के कारण पुलिस की चुनौतियां बढ़ गई है ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह के उन्माद फैलाने वाली सुचनाओं के भ्रामक प्रचार को रोकना भी जरुरी हो गया है इसके लिए पुलिस को और सक्रियता बढ़ाकर सकारात्मक प्रयास करने के निर्देश दिए।

चिरमिरी के जनता के साथ हुआ विश्वासघात जनता नही करेगी माफ : महेश प्रसाद

चिरमिरी। एसईसीएल क्षेत्र जो कोलांचल की नगरी कहां जाता था आज इस मुकाम में पहुंच चुका है चिरमिरी को बचाना मुस्किल हो रहा है और जनसंख्या की बात करे दिन प्रतिदिन जनसंख्या कम होने के कारण व्यापार में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। चिरमिरी को बचाना बहुत ही जरूरी है। इस क्षेत्र को बचाना कैसे है अगर इस ओर जनप्रतिनिधियों का ध्यान गया होता तो शायद आज चिरमिरी की दशा कुछ और होता। मगर सत्ते नशे में चूर उन्होंने अपने ही घर को नही छोड़ा चिरमिरी की जनता से विकाश के नाम पर केवल वोट लेकर सत्ता का सुख भोगने का काम किया और उन्होंने जेब का विकास किया है चिरमिरी की भोली भाली जनता को इन्होंने छला है विश्वासघात किया है। जो चिरमिरी की जनता इन्हे कभी माफनहीं करेगा इनके पास एक मौका था चिरमिरी में रोजगार लाकर चिरमिरी को बचाया जा सकता था लेकिन उन्होंने चिरमिरी के माटी के साथ धोखा दिया है जो चिरमिरी की जनता कभी नहीं भुलाएगी अगर बात करे वर्तमान विधायक की इनके ही वरिष्ट कांग्रेसियों का कहना है हमारे विधायक नाकाम रहे पूरे विभाग हमारे हाथ से चले गए क्या जनता के साथ विश्वासघात करना सही है सरकार इनकी विधायक इनकी महापौर भी इनका विकास भी केवल इनका चिरमिरी में एसईसीएल का सड़क एसईसीएल का बिजली एसईसीएल पानी एसईसीएल का घर न जाने आज एसईसीएल न होता तो यहां के बेरोजगारों का क्या होता चिरमिरी के आधे से ज्यादा जनसंख्या एसईसीएल के भरोसे है । चिरमिरी के माटी से बने माटी पुत्र शायद चिरमिरी के माटी का मूल्य भूल चुके हैं जिसने उन्हें नाम दिया पहचान दिलाई आज वही चिरमिरी के अस्तित्व की रक्षा नही कर पा रहे हैं। यदि चिरमिरी में एस ई सी एल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता तो विद्यायक महोदय एस ई सी एल कार्यालय को ताला लगा देते हैं। लेकीन निगम द्वारा बार बार गलतियां करने पर भी विधायक के कानो में जू तक नही रेंगी।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

कांग्रेस ने पीएम से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की

नईदिल्ली। कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने एक ट्वीट में कहा, मणिपुर पिछले 40 दिनों से जल रहा है और संघर्ष नियंत्रण से बाहर हो रहा है। कानून के शासन का कोई आभास नहीं है और जो सत्ता में हैं वे स्वयं नरसंहार कर रहे हैं और हथियारों और गोला-बारूद के साथ उग्रवादियों की मदद कर रहे हैं। मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने पूरी तरह चुप्पी साध रखी है और उनकी सरकार ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। केंद्र सरकार इसे जारी क्यों रहने दे रही है? इस विनाशकारी स्थिति के लिए कौन जवाबदेह हैं? प्रधानमंत्री को तुरंत एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए क्योंकि देश जवाब मांग रहा है। क्या वह आखिरकार एक केंद्रीय मंत्री के आवास पर हमला होने के बाद बोलेंगे?कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर सरकार की आलोचना की। चिदंबरम ने एक ट्वीट में कहा, कर्नाटक में डबल इंजन सरकार विफल रही और कर्नाटक के लोगों ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया।

नेहरू का नाम हटाने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

नईदिल्ली। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी (एनएमएमएल) का नाम बदलने के केंद्र के फैसले की निंदा करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा, आपका नाम मोदी है। इसके अलावा, जयराम रमेश ने कहा कि परिसर पिछले 59 वर्षों से पुस्तकों और अभिलेखागार का खजाना रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और कहा कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी एक वैश्विक बौद्धिक मील का पत्थर और पुस्तकों और अभिलेखागार का खजाना घर रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, मोदी भारतीय राष्ट्र-राज्य के वास्तुकार के नाम और विरासत को विकृत, तिरस्कृत और नष्ट करने के लिए क्या नहीं करेंगे। एक छोटा, छोटा आदमी अपनी असुरक्षा से दबकर स्वयंभू विश्वगुरु है।

इस बार लोकसभा चुनाव में ना हो चूक : अखिलेश यादव

लखनऊ। चुनावों में लगातार मिल रहे शिकस्त से सबक़ लेते हुए अब सपा मुखिया अखिलेश यादव अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। अखिलेश यादव पार्टी के भीतर कील-कांटे दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुटता बनाये रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिहाज से यह चुनाव आने वाली पीढ़ी और देश का भविष्य तय करेंगे। पार्टी मुख्यालय में बड़ी तादाद में आये सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी में अब आपसी गुटबंदी नहीं चलेगी। कार्यकर्ता इस बार चूक न करें बूथ स्तर पर लोकतंत्र को बचाना है। लोकसभा चुनाव बहुत ही गंभीरता से लड़ना और जीतना है। अखिलेश ने कहा कि 2024 में होने वाले चुनाव आने वाली पीढ़ी और देश का भवष्यि भी तय करने वाले साबित होंगे।

नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल हुए रत्नेश सदा

पटना। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार वाली कैबिनेट का विस्तार किया गया। जदयू विधायक रत्नेश सदा को कैबिनेट में शामिल किया गया। शुक्रवार को पटना स्थित राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ जिसमें राज्यपाल ने जदयू विधायक रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य नेता उपस्थित रहे। बिहार में फिर एकबार सियासी फेरबदल हुआ है और जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने महागठबंधन से किनारा कर लिया। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद अब जदयू विधायक रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया है। रत्नेश सदा भी महादलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वो सहरसा के सोनबरसा से विधायक हैं। रत्नेश सदा जदयू के महादलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं और उनका सियासी सफर बेहद शानदार रहा है।

बंगाल में राजनीतिक हिंसा खत्म होनी चाहिए : राज्यपाल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने शुक्रवार को दक्षिण 24 परगना जिले में भंगोर का दौरा करने के बाद कहा कि राज्य में राजनीतिक हिंसा हर हाल में खत्म होनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि वह पहले ही मौजूदा स्थिति पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ चर्चा कर चुके हैं। भंगोर में स्थिति का जायजा लेने के बाद बोस ने संवाददाताओं से कहा, 'बंगाल के कुछ हिस्सों में कुछ अवांछित घटनाएं हुई हैं। किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हमें इसे रोकना होगा।' स्थिति पर चर्चा का हवाला देते हुए बोस ने कहा, 'मुख्यमंत्री मेरी संवैधानिक सहयोगी हैं। हमने जो चर्चा की, उसे सार्वजनिक तौर पर साझा नहीं किया जा सकता।' उन्होंने कहा, 'निश्चित रूप से, संविधान के तहत राज्यपाल से जो भी उम्मीद की जाती है, वह किया जाएगा।'उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव के नामांकन दाखिल करने के दौरान भंगोर के अलावा अन्य जिलों में भी हिंसक झड़प हुई।

जीतनराम महागठबंधन की जासूसी कर रहे थेः नीतीश

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लाभ पहुंचाने के लिये महागठबंधन के सहयोगियों की जासूसी करने का आरोप लगाया और दावा किया कि महागठबंधन से उनका बाहर निकलना अच्छी बात है। नीतीश कुमार ने स्वीकार किया कि पूर्व मुख्यमंत्री मांझी 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें (नीतीश को) डर था कि उनके (मांझी) द्वारा बैठक का विवरण भाजपा को लीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा, वह (मांझी) भाजपा नेताओं के लगातार संपर्क में थे।

उन्होंने हाल ही में कई भाजपा नेताओं से मुलाकात की थी। वह 23 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन मुझे आशंका थी कि वह उन मुद्दों/मामलों को लीक कर सकते हैं जिन पर 23 जून को चर्चा की जाएगी। सोनबरसा विधानसभा सीट से जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक रत्नेश सदा के राज्य मंत्रिमंडल में

शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, इसलिए, मैंने उनसे हम (सेक्यूलर) का जद (यूनाइटेड) में विलय करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकते, इस पर, मैंने उनसे महागठबंधन छोड़ने के लिए कहा।

यह अच्छा है कि वह महागठबंधन छोड़कर चले गए। सोनबरसा विधानसभा सीट से तीन बार विधायक रहे रत्नेश सदा मुसहर जाति से हैं, उन्हें राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी ने हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हुए कहा था, नीतीश कुमार की जद (यू) द्वारा हम (सेक्यूलर) का उसके जद (यू) में विलय करने का प्रस्ताव देने के बाद मैंने पार्टी को बचाने के लिये मंत्री पद छोड़ दिया।

कुमार ने कहा, हमारी पार्टी ने मांझी को बहुत कुछ दिया है। उनकी पार्टी को जद (यू) के कोटे से राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री पद दिया गया था। इन सबके बावजूद... वह भाजपा नेताओं के संपर्क में थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, इस बात की प्रबल संभावना है कि आम चुनाव अगले साल ना हों। ये पहले भी हो सकते हैं। इसलिए सभी विपक्षी दलों को आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा को हराने के लिए एक साथ आना चाहिए। हमें 23 जून की बैठक के बाद तैयारी शुरू करनी चाहिए।

बंगाल हिंसा को लेकर भाजपा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना

नईदिल्ली। बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से ही लगातार हिंसा जारी है। इस चुनावी हिंसा को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली स्थित पार्टी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सभी विपक्षी दलों से यह सवाल किया कि क्या विपक्षी दलों को पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र में कोई समस्या नजर नहीं आ रही।

डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, हिंसा का जो तांडव दिखाई पड़ रहा है, यह कष्टकारक है। इससे भी अधिक दुखद है, वहां की सरकार की असंवेदनशीलता। हमारे कार्यकर्ताओं पर प्राणघातक हमले हुए हैं। इस दौरान उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले में हुई हिंसा का भी जिक्र किया।

बंगाल हिंसा, चुनावी इतिहास में एक काला अध्याय

डॉ त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस जिस प्रकार से बर्ताव कर रही है वो भारत के लोकतांत्रिक और चुनावी इतिहास में एक बहुत ही काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि बंगाल में 341 ब्लॉक हैं। आखिरी दिन यहां, 4 घंटे के अंदर 40 हजार से अधिक लोगों ने नामांकन किया है, वो भी 340 ब्लॉक में, यानी एक व्यक्ति के नामांकन का समय औसतन 2 मिनट आता है। इस गति से हुए नामांकन दर्शाते हैं कि स्थानीय सरकार किस तरह से व्यवस्था को अपने हाथ में लिए हुए है। क्या यह लोकतंत्र का उपहास नहीं है?

चिंगारी का खेल बुरा होता है

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा मैं टीएमसी को यह कहना चाहता हूं कि यह हिंसा का जो खेल आप खेल रहे हैं, ऐसा ही कम्युनिस्ट सरकार करती थी। आज आप उनका हाल देख लीजिए। अटल जी की लिखी पंक्तियां हैं कि- चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना..अपने घर में ही अक्सर खरा होता है।

सभी विपक्षी दलों से सवाल?

डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा मैं समस्त विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं- लोकतंत्र का हिंसा से घायल स्वरूप आज जो पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, जो मां, माटी, मानुस की बात करती थीं, आज वह भारत मां के विरुद्ध शक्तियां खड़ी हो रही हैं, माटी खून से सनी है और मनुष्यता पूरी तरह से व्यथित और कलंकित नजर आ रही है।।। उसको देख कर भी, किसी विपक्षी दल को कोई समस्या नजर नहीं आ रही है?

ममता बनर्जी की सरकार दमनकारी सरकार

पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में जिस तरह के नजारे देखने को मिल रहे हैं वो बेहद दर्दनाक हैं। यहां चारों ओर हिंसा है। इससे भी ज्यादा निराशाजनक वहां की सरकार की संवेदनहीनता है। डॉ त्रिवेदी ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार दमनकारी सरकार है। एक समय था उन्होंने कम्युनिस्टों का दमन झेला था, तब बीजेपी ने ही उनकी मदद की थी और अब वह खुह कम्युनिस्टों की राह पर चल रही हैं।

लोकतंत्र फल-फूल रहा है या लुप्त हो रहा है?

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र लगभग समाप्त हो गया है, मैं उनसे एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल है कि पश्चिम बंगाल में जिस स्तर की हिंसा देखी जा रही है, वह क्या दर्शाती है? वह लोकतंत्र फल-फूल रहा है या लुप्त हो रहा है?

हमारी विभिन्न योजनाओं की वजह से आज पूरे देश में राजस्थान की चर्चा है: गहलोत

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के चलते आज पूरे देश में राजस्थान की चर्चा है। उन्होंने कहा कि लंपी रोग से दुधारू गायों की मौत पर 40-40 हजार रुपये का मुआवजा देने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। गहलोत ने यहां मीडिया से बातचीत में अपनी सरकार के महंगाई राहत शिविरों का जिक्र किया। उन्होंने कहा,''इन शिविरों में सात करोड़ गारंटी कार्ड बंट चुके हैं, 1.60 करोड़ घर में हम लगभग पहुंच चुके हैं. इतना बड़ा अभियान चल रहा है। पूरे देश में चर्चा किसी राज्य की है तो उस राज्य का नाम राजस्थान है।

फिर चाहे 25 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा की बात हो या पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की चर्चा हो। और भी कई योजनाएं हैं आठ-दस योजनाएं ऐसी हैं जो सिर्फ राजस्थान में शुरू हुई हैं।'' उन्होंने कहा,''(राजस्थान) पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब कई राज्यों में बनने वाले चुनावी घोषणा पत्रों का आधार राजस्थान की योजनाएं ही हैं।'' इससे पहले गहलोत ने राजस्थान किसान महोत्सव को संबोधित किया और उन 41 हजार से अधिक किसानों/पशुपालकों के खातों में 175 करोड़ रुपये से अधिक की प्रत्यक्ष राशि अंतरित (डीबीटी) की जिनकी दुधारू गायों की मौत गांठदार लंपी रोग से हो गई।

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर गहलोत को खुली बहस की चुनौती दी

जयपुर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाला मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुली बहस करने की चुनौती दी है। गहलोत द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बृहस्पतिवार को पोकरण में मीडिया से कहा, आज चुनौती देकर यहां से कहता हूं, वो और उनके वकील हिंदुस्तान के किसी भी मंच पर खड़े हो जाएं और वहां खड़े होकर मेरे सामने इस पर बहस करें। वकीलों को लेकर बहस करें, मुझे किस तरह से दोषी ठहरा रहे हैं

उल्लेखनीय है कि गहलोत ने जोधपुर से सांसद शेखावत पर बार बार इस घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है जिसमें बड़ी संख्या में निवेशकों को करोड़ों रुपये का चूना लगा। शेखावत ने उन्हें क्रेडिट सोसाइटी से जोड़ने के आरोपों को खारिज करते हुए गहलोत के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। शेखावत ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने बेटे वैभव गहलोत की हार के कारण उन पर आरोप लगाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने जोधपुर लोकसभा सीट पर वैभव को हराया था। जोधपुर गहलोत का गृहनगर भी है। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि वह भाजपा के राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा द्वारा गहलोत और उनके बेटे के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करेंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

लियोनेल मेसी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दागा सबसे तेज गोल

बीजिंग। अर्जेंटीना को फीफा का विश्व खिताब जीताने में अहम भूमिका निभाने वाले लियोनेल मेसी इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में चल रहे है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लियनेल मेसी का बेहद शानदार फॉर्म आमतौर पर हर ही मुकाबले में देखने को मिल रहा है। ऐसा ही फॉर्म लियोनेल मेसी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भी दिखाया।

दरअसल इन दिनों लियोनेल मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोस्ताना मैच खेलने के लिए बीजिंग गई हुई है। इस मुकाबले का आयोजन 15 जून को किया गया। इस मुकाबले में लियोनेल मेसी ने अपनी टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलवाई। मुकाबले में उन्होंने 79वें सेकेंड में ही जोरदार गोल दागा, जिससे फैंस काफी खुश हुए। लियोनेल मेसी का गोल करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मेसी का ये गोल दूसरे मिनट में आया। इस गोल को एंजो फर्नांडेज ने असिस्ट किया था। इस गोल के लिए एक कर्लिंग शॉट लगाने से पहले अर्जेंटीना के स्टार ने कुशलता से दो डिफेंडरों को चकमा दिया। इसके बाद उन्होंने टीम के लिए एक और अहम गोल सेट करने में मदद की। इसके बाद अर्जेंटीना की तरफ से दूसरा गोल मैच के 68वें मिनट में किया गया था। इस बार गोल बनाने के लिए मेसी ने मदद की। लंबे समय तक बाएं कॉर्नर के नजदीक लियोनेल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को छकाते रहे। इसके बाद उन्होंने गेंद रोड्री डी पॉल को पास की। डी पॉल ने गोलपोस्ट के तरफ से गेंद जर्मन पेजेला को दी जिन्होंने क्रॉस पर हेडर से गोल कर दिया। गौरतलब है कि अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला मैत्री मैच का था। इस मुकाबले के लिए भी फुटबॉल प्रेमियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। फैंस बड़ी संख्या में अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी को देखने मैदान में पहुंचे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 63,384 पर, निफ्टी 18,800 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच आज घरेलू शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिली। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स 466.95 अंक की उछाल के साथ ऑलटाइम हाई पर बंद हुआ। निफ्टी भी 137.90 अंक चढ़कर 18,826 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 466.95 अंक यानी 0.74 फीसदी की बढ़त के साथ 63,384.58 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 63,520.36 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 62,957.17 तक आया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 137.90 अंक यानी 0.74 फीसदी चढ़ा। निफ्टी दिन के अंत में 18,826.00 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 18,864.70 की उंचाई तक गया और नीचे में 18,710.50 तक आया।

जीएसटी काउंसिल की बैठक 11 जुलाई को

नईदिल्ली। जीएसटी काउंसिल 11 जुलाई को फर्जी पंजीकरण और इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पर नकेल कसने के लिए कुछ और उपायों पर चर्चा करेगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन विवेक जौहरी ने संवाददाताओं से कहा, 'हम कर चोरी रोकने के लिए कुछ अन्य उपायों पर विचार कर रहे हैं और उन्हें कानून समिति तथा जीएसटी काउंसिल की उचित प्रक्रिया के जरिए अमल में लाया जाएगा।' जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक 11 जुलाई को होनी है। परिषद ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ पर कर लगाने के मुद्दे पर जीओएम की रिपोर्ट पर भी चर्चा करेगी। मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने पिछले साल दिसंबर में परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन परिषद ने इसे चर्चा के लिए नहीं लिया है।

भारत, चीन ने मई में रूस का 80 फीसदी तेल खरीदा: आईईए

नईदिल्ली। दुनिया के शीर्ष तेल उपयोगकर्ताओं भारत और चीन ने मई में रूस का 80 प्रतिशत तेल खरीदा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने एक रिपोर्ट में कहा कि मॉस्को ने यह जानकारी दी। गौरतलब है कि रूस दोनों देशों को भारी छूट के साथ कच्चा तेल दे रहा है। पेरिस स्थित ऊर्जा एजेंसी ने तेल बाजार रिपोर्ट में कहा, भारी छूट वाले रूसी कच्चे तेल को मुख्य रूप से एशिया में नए खरीदार मिले हैं। भारत जहां पहले रूस से न के बराबर खरीदारी करता था, वहीं अब वह प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल तेल खरीद रहा है। दूसरी ओर चीन ने खरीदारी बढ़ाकर पांच लाख बैरल प्रतिदिन से 22 लाख बैरल प्रतिदिन कर दी है। मई में रूस के समुद्री कच्चे तेल का निर्यात औसतन 38.7 लाख बैरल प्रतिदिन रहा, जो फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद सबसे अधिक है। आईईए ने कहा, मई 2023 में, भारत और चीन की रूसी कच्चे तेल के निर्यात में लगभग 80% हिस्सेदारी थी।

बीमा सुगम के अगस्त तक शुरू होने की संभावना कम

नईदिल्ली। किफायती बीमा सुविधा 'बीमा सुगम' के अगस्त तक शुरू होने की संभावना कम हो गई है क्योंकि बीमा नियामक इरडा इसे अधिक कारगर बनाने के लिए इसमें कुछ संशोधन कर रहा है। बीमा सुगम बाजार में आने के बाद किसी ई-कॉमर्स मंच की तरह ऑनलाइन बीमा बाजार के तौर पर काम करेगा। इसके माध्यम से बीमा जारीकर्ता के पास अपने उत्पादों की पेशकश करने और उन्हें बेचने का अवसर होगा। इसके साथ ग्राहक एक ही स्थान पर बीमा योजनाएं खरीद सकेंगे या उनका नवीनीकरण करा सकेंगे, अपना दावा पेश कर सकेंगे और अन्य संबंधित सेवाएं भी ले सकेंगे। इरडा के चेयरमैन देबाशीष पांडा ने बीमा सुगम परियोजना को नया रूप देने और इसे एक अगस्त से शुरू करने के लिए पिछले महीने मुंबई में कुछ प्रमुख बीमा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी।

लॉजिस्टिक लागत घटने से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था

डॉ जयंती लाल भण्डारी

इस समय लॉजिस्टिक लागत से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में कमी करके उत्पादकता और निर्यात तेजी से बढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ-साथ यातायात प्रबंधन में सुधार करके जहां लॉजिस्टिक लागत को और कम किया जा सकता है, वहीं समय व ऊर्जा की बचत करते हुए दुर्घटनाओं में भी कमी लाई जा सकती है। ऐसे में आम आदमी से लेकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लाभान्वित किया जा सकता है।

गौरतलब है कि देश में पिछले एक-दो वर्षों में लॉजिस्टिक लागत में कुछ कमी दिखाई देने लगी है। हाल ही में प्रकाशित विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 6 पायदान की छलांग के साथ 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत 2018 में इस सूचकांक में 44वें तथा 2014 में 54वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अक्तूबर 2021 में घोषित पीएम गति शक्ति योजना और सितंबर 2022 में घोषित राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) के कार्यान्वयन और वर्ष 2020 से लागू उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के प्रारंभिक अपेक्षित परिणामों से लॉजिस्टिक लागत में कमी आने का परिदृश्य निर्मित होने लगा है।

ज्ञातव्य है कि विश्व बैंक के ताजा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के तहत कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों, बुनियादी ढांचे, अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट और लॉजिस्टिक क्षमता संबंधी भारत की बढ़त दुनियाभर में रेखांकित हो रही है। आधुनिकीकरण व डिजिटलीकरण से भी भारत का लॉजिस्टिक प्रदर्शन बेहतर

हुआ है। सामान्यतया वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल की लागत पहले क्रम पर और मजदूरी की लागत दूसरे क्रम पर होती है। फिर लॉजिस्टिक लागत का क्रम आता है।

लॉजिस्टिक लागत का मतलब है उत्पादों एवं वस्तुओं को उत्पादित स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंचाने तक लगने वाले परिवहन, भंडारण व अन्य खर्च। लॉजिस्टिक लागत कम या अधिक होने में बुनियादी ढांचे की अहम भूमिका होती है। यदि सड़कें बेहतर और अन्य बुनियादी ढांचे की सुविधाएं उपयुक्त हों तो तेजी से सामान पहुंचने, परिवहन संबंधी चुनौतियां और ईंधन की लागत कम होने से भी लॉजिस्टिक लागत कम हो जाती है। यदि निर्धारित समय में बुनियादी ढांचे संबंधी परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं तब भी लॉजिस्टिक लागत में कमी आती है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की गति शक्ति योजना करीब 100 लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका लक्ष्य देश में एकीकृत रूप से बुनियादी ढांचे का विकास करना है। वस्तुतः देश में सड़क, रेल, जलमार्ग आदि का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह अलग-अलग 16 मंत्रालयों और विभागों के अधीन है, उनके बीच में सहकार व समन्वय बढ़ाना गति शक्ति योजना का मुख्य फोकस है। असल में नई लॉजिस्टिक पॉलिसी गतिशक्ति योजना की अनुपूरक है। इसका प्रमुख लक्ष्य माल परिवहन की लागत घटाकर सभी प्रकार के उद्योग-कारोबार को बढ़ावा देना और वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना भी है। देश में नई लॉजिस्टिक नीति के जरिये अगले 10 सालों में लॉजिस्टिक्स सेक्टर की लागत को 10 प्रतिशत तक लाया जाएगा। चूंकि वर्तमान में लॉजिस्टिक्स का ज्यादातर काम सड़कों के जरिये होता है, अतएव अब नई नीति के तहत रेल ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया जा रहा है। लगभग 50 प्रतिशत कार्गो को रेलवे के जरिये भेजे जाने का लक्ष्य आगे बढ़ाया जा रहा है और सड़कों पर ट्रैफिक को कम किया जा रहा है। हम उम्मीद करें कि सरकार ऐसी नई रणनीति पर आगे बढ़ेगी जिससे विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 38वें स्थान के बाद अब आगामी 2027 के सूचकांक में भारत की और ऊंची छलांग लग सकेगी। साथ ही इससे महंगाई में कमी, रोजगार में वृद्धि और जीडीपी में तेज वृद्धि के कारण विकास के नए अध्याय भी लिखे जा सकेंगे।

कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं मुस्लिम वोटर

संतोष पाठक

देश में ब्रिटिश काल के दौरान हुए चुनावों में जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के आक्रामक प्रचार अभियान के बावजूद भी मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा तबका कांग्रेस को ही वोट दिया करता था। 1947 में देश आजाद हुआ। जिन्ना की मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मिल गया लेकिन आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में हुए चुनावों में मुसलमानों ने पूरी तरह से कांग्रेस को ही वोट किया। कांग्रेस ने ब्राह्मण सहित कई अगड़ी जातियों, मुसलमानों और दलितों के बड़े वोट बैंक के आधार पर दशकों तक देश पर राज किया। 1967 में विपक्षी दलों की गोलबंदी के कारण कई राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पहली बार केंद्र की सत्ता से बाहर होना पड़ा। लेकिन सही मायनों में कांग्रेस के कमजोर होने की शुरूआत 1990 के दशक में ही शुरू हुई। जब मुसलमान वोटरों ने जेपी के आंदोलन से निकले और आगे चलकर मंडल की राजनीति के पुरोधा बने मुलायम सिंह यादव और लालू यादव को अपना नेता मान कर, उन्हे वोट देना शुरू किया। मुस्लिम वोटर पहले जनता दल के खाते में गए और जैसे-जैसे जनता दल से टूटकर नए-नए दल बनते चले गए वैसे-वैसे मुस्लिम वोटर भी उनके साथ जुड़ते चले गए। इसके बाद दलित वोटर भी कांग्रेस का साथ छोड़कर बसपा के साथ चले गए। बसपा ने कांशीराम के जमाने में देश की राजनीति में सबसे पहला धमाका पंजाब में किया और उसके बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में आकर जम गई। आज भी अपने सबसे मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश में कमजोर होने और लगातार चुनाव हारने के बावजूद लोकसभा में बसपा के 10 सांसद है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अलावा बसपा देश के जिस राज्य में भी चुनाव लड़ती है, वहां भी उसे 5 से 8 फीसदी वोटरों का वोट मिलता है जो आमतौर पर दशकों तक कांग्रेस को वोट करता रहा है। कांग्रेस के लगातार कमजोर होने और दिशाहीन होते चले जाने के बाद सबसे आखिर में ब्राह्मण वोटरों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कई वजहों से धीरे-धीरे कांग्रेस फिर से अपने पुराने वोट बैंक को लुभाती नजर आ रही है। सबसे पहले बात देश के एक बड़े वोट बैंक की करते है जिसके बारे में यह माना जाता है कि वो थोक में एक साथ वोट करते हैं- मुस्लिम वोटर। देश की तेजी से बदल रही राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि देश के वोटरों का अब क्षेत्रीय दलों से मोहभंग होता जा रहा है और मुस्लिम वोटर एक बार फिर से कांग्रेस का हाथ थामने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक के विधानसभी चुनाव में देखने को मिला। कर्नाटक की राजनीति में आमतौर पर मुस्लिम वोटर कांग्रेस और जेडीएस में बंटे हुए थे। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक के मुस्लिम वोटरों ने जेडीएस का साथ छोड़कर पूरी तरह से कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में वोट किया और इस का नतीजा यह रहा कि दक्षिण भारत के अपने सबसे मजबूत गढ़ में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा।

कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द होगा

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा की 66 सीटें पाकर सत्ता से बाहर हो गई। देश ने देखा भी कि जब इलेक्शन के परिणाम घोषित हो रहे थे तब कांग्रेस के नेताओं के साथ आम कार्यकर्ताओं के चेहरे पर एक अलग प्रकार की खुशी थी। कई कार्यालयों में हनुमान जी की गदा कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं के हाथों में लहरा रही थी और दावे यही किए जा रहे थे कि बजरंगबली का साथ भाजपा को नहीं कांग्रेस को कर्नाटक में मिला और वह सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन उन्हीं बजरंगबली को पूजनेवाले बहुसंख्यक समाज की रक्षा करने एवं उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जिस संविधानिक व्यवस्था से धर्मांतरण विरोधी कानून कर्नाटक में पिछली भाजपा सरकार लाई थी, आज उसी को नई कांग्रेस सिद्धारमैया सरकार रद्द करने जा रही है।

सही भी है, सत्ता जिसकी, निर्णय भी उसका । किंतु क्या यह सिद्धारमैया सरकार उन मुट्ठीभर मुसलमानों के भरोसे आई है, जोकि इस कानून के बनने के पहले दिन से ही इसका विरोध कर रहे थे क्या यह कांग्रेस सरकार का निर्णय उन बहुसंख्यक हिन्दुओं को फिर एक संघर्ष की आग में झोंक देने वाला नहीं होगा जिसमें प्रशासन अब तक कानून होने के कारण सहयोग करता रहा और अब तक कई लव जिहाद या अन्य इसी प्रकार के मामलों में बेटियां बचाई जाती रहीं । क्या इस एक निर्णय से पुन: ऐसी घटनाओं को बढ़ने से रोका जा सकेगा प्रश्न अनेक हो सकते हैं, लेकिन इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है कि कानून का भय समाप्त होते ही लव जिहादी पहले से ओर अधिक खुला घूमेंगे।

कहना होगा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर हिन्दुओं को उन तमाम विवादों में झोंक दिया है, जिससे वे राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून होने के कारण से बचते आ रहे हैं । हम सभी जानते हैं कि कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून 2022 में लाया गया था, इसके बाद पूर्व की तुलना में ऐसे मामलों में कमी देखी गई, जिसमें कि एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन, किसी के प्रभाव में या बहकाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। वस्तुत: पूर्व की भाजपा सरकार ने ऐसा करना गैर कानूनी बना दिया था । यहां जो धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करता पाया जाता, उसे इसके अंतर्गत तीन

से पांच साल की कैद और 25000 रुपये जुर्माना देना अनिवार्य कर दिया गया था।

इतना ही नहीं तो इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया । सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए तीन से दस साल तक की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। यह भी कहा गया कि कोई भी शादी जो धर्म परिवर्तन के इरादे से ही की गई है, उसे फैमिली कोर्ट द्वारा अवैध माना जाएगा और ऐसा किया जाना गैरजमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया।

वास्तव में इस कानून के प्रभाव से यहां देखने में आया कि जब से यह कानून बना, राज्य में ऐसे मामलों में अचानक से कमी आ गई थी। फिर भी इसमें जो सबसे अधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए, उनमें लव जिहाद के ही सबसे अधिक रहे, इसमें धर्मांतरण के मामलों में शिकार अधिकतम हिन्दू ही बने, जिसकी शिकायत होने पर पुलिस ने इस कानून में नियमानुसार अपनी कार्रवाई भी की । लेकिन अब आगे से यह कानून समाप्त हो रहा है। इसके साथ कानून के नियमन से व्याप्त होनेवाला भय भी समाप्त हो जाएगा। अब इसके समापन का नकारात्मक प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ेगा स्वभाविक उत्तर है, कर्नाटक के बहुसंख्यक हिन्दू समाज पर । यहां फिर से लव जिहाद एवं धर्मांतरण के मामले बढ़ जाएंगे। हिन्दुओं तुम अपने लिए न्याय पाने पुलिस थानों के चक्कर लगाना, हाथ जोड़ना, गुहार लगाना, लेकिन अब इस प्रकार का कोई कानून नहीं होगा जो तुम्हें तुम्हारे साथ हुए छल से तुम्हें कुछ राहत प्रदान कर सके ।

यह कुछ घटनाएं पिछले साल की हैं, जिनका उदाहरण यहां देना समीचीन होगा। पिछले साल कर्नाटक के मांड्या जिले में 13 साल की नाबालिग लड़की से ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म का मामला सामने आया । पता चला वह %लव जिहाद% की शिकार हुई थी, एक 25 वर्षीय आरोपी ने दुष्कर्म के बाद पीड़िता को इस्लाम कबूल करने और उससे शादी करने के लिए नाबालिग को प्रताड़ित किया था। एक अन्य घटना में हुबली में मोहम्मद एजाज शिरूर से शादी करने के बाद इस्लाम धर्म अपनाने वाली अपूर्वा पुराणिक को तलाक लेने के लिए 20 बार चाकू मारा । एजाज पहले से ही शादीशुदा था और उसके दो बच्चे हैं। जांच से पता चला कि ऑटो चालक एजाज ने एमबीए स्नातक युवती को फंसाया, उसके निजी वीडियो बनाए, ब्लैकमेल किया और शादी के लिए फुसलाया था ।

वस्तुत: अकेले कर्नाटक राज्य में लव जिहाद से जुड़े ऐसे अनेकों प्रकरण अब तक दर्ज हो चुके हैं। पता नहीं राज्य के किस कौने में इस समय भी कोई बेटी, लव जिहाद की शिकार बनाई जा रही होगी! इस ठगी का कोई ठिकाना नहीं। सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं देश भर में मुस्लिम युवाओं को हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए प्रशिक्षित किया जाने के आज अनेकों मामले प्रकाश में आ चुके हैं। इसके पीछे काम करने वाले संगठन न केवल युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं, वे उन्हें बाइक, नकदी और फैशनेबल पोशाक भी प्रदान करते हैं।

इस विशेष प्रशिक्षण का परिणाम यह है कि हिन्दू लड़कियां इनके झांसे में आ जाती है, जब तक इनके गैर हिन्दू होने का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हिन्दू परिवारों में यह सिखाना कि सभी मत, पंथ धर्म समान होते हैं, वह तो बाद में जब व्यवहार में आता है तब पता चलता है कि हकीकत क्या है तब तक एमबीए, इंजीनियरिंग और स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही हिंदू लड़कियां मैकेनिक, राजमिस्त्री और ऑटो चालकों के झांसे में आ रही हैं। ऐसे अनेकों मामले हैं। इस प्रयास को मुस्लिम समुदाय और आरोपितों के परिजनों का समर्थन मिलता हुआ भी देखा गया है। जो ऐसा करने का समर्थन करते हैं, वे इसे अपनी आबादी बढ़ाने का एक हिस्सा मानते हैं।

इसके आगे यह भी एक सच है कि धर्म परिवर्तन के लिए हिंदू लड़कियों, महिलाओं को फंसाना एक बात है, किंतु उनका इस्तेमाल लाइव बॉम्बर्स के रूप में किया जाना भी सामने आ चुका है। हुबली में प्रसिद्ध बेकरी मालिक की बेटी किसी के साथ भाग जाने के बाद लापता थी, 15 साल बाद उसकी तस्वीर 1999 में कोयम्बटूर विस्फोट मामले के वांछित व्यक्तियों की सूची में दिखाई दी थी, उसे 10 वांछित व्यक्तियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यह साक्ष्य है कैसे हिंदू लड़कियों का उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाता है। हिंदू लड़कियों को अगवा करने और लव जिहाद में फंसाने के बाद उन्हें सीरिया भेजे जाने के प्रकरण भी आज सामने आ चुके हैं।

कई प्रकरणों में नाबालिग लवजिहाद की शिकार होकर पुलिस के पास मामला दर्ज कराने पहुंची हैं और कई में पुलिस नाबालिग को खोजकर मुस्लिम बस्तियों एवं अन्य स्थानों से लेकर आई और उसे उसके माता-पिता को सौंपा है। आज भी यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। प्रकरणों का आना बंद नहीं हुआ है, हां, कर्नाटक में इतना जरूर हुआ है कि धर्मांतरण कानून के भय से ऐसे प्रकरणों में कमी जरूर आई, अब कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून के रद्द होने के बाद फिर से ऐसे मामलों में बढ़ोत्तरी हो जाएगी । जिनकी नाबालिग लड़की भी इसका बहुतायत में शिकार होंगी, उसका परिवार पुलिस थानों के चक्कर लगाता नजर आएगा, पहले कानून का भय था, अब ऐसे लव जिहाद करनेवाले अपराधियों को किसी का भय नहीं होगा।

अंत में यही कि सनातन धर्म यानी कि हिन्दू धर्म में बजरंगबली रहेंगे, उनकी पूजा भी होती रहेगी, लेकिन उनकी गदा जोकि शक्ति का प्रतीक है और एक तरह से आज के समय में कानून का स्वरूप है। वह कानून रूपी गदा अब बजरंग बली के पास नहीं रहेगी! हिन्दुओं के आराध्य बजरंगबली अब शक्ति रूपी इस गदा के बिना कर्नाटक में कैसे अर्धर्मी से किसी युवती की रक्षा कर पाएंगे, यही आज का यक्ष प्रश्न है, जिसके बारे में अब उन तमाम हिन्दुओं को सोचना है, जिन्होंने छोटे-छोटे सत्ता में किए गए वादों के चलते कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन में अपनी आहुती दी है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

गायत्रीरहस्योपनिषद् (भाग-4)

गतांक से आगे...

पन्द्रहवें के वामदेव, सोलहवें के मैत्रावरुण, सत्रहवें के भ्रातृव्य, अठारहवें के विष्णु, उन्नीसवें के वामन, बीसवें के वैश्वदेव, इक्कीसवें के रुद्रदेव, बाइसवें के कुबेर, तेईसवें के अश्विनीकुमार और चौबीसवें अक्षर के ब्रह्मदेव शक्तिरूप हैं-यही प्रत्येक अक्षर के देवता कहे गये हैं।

(अब गायत्री के 24 अक्षरों के 24 ऋषियों का वर्णन करते हैं -) इसके प्रथम अक्षर के ऋषि वसिष्ठ, दूसरे के भरद्वाज, तीसरे के गर्ग, चौथे के उपमन्यु, पाँचवें के भृगु (भार्गव), छठे के शाण्डिल्य, सातवें के लोहित, आठवें के विष्णु, नौवें के शातातप, दसवें के सनत्कुमार, ग्यारहवें के वेदव्यास, बारहवें के शुकदेव, तेरहवें के पाराशर, चौदहवें के पौण्ड्रक, पन्द्रहवें के ऋतु, सोलहवें के दक्ष, सत्रहवें के कश्यप, अठारहवें के अत्रि, उन्नीसवें के अगस्त्य, बीसवें के उद्दालक, इक्कीसवें के आङ्गिरस, बाइसवें के नामिकेतु, तेईसवें के मुद्गल और चौबीसवें के अङ्गिरा गोत्रज विश्वामित्र हैं, यही प्रत्येक अक्षरों के अलग-अलग चौबीस ऋषि होते हैं।

गायत्री, त्रिष्टुप् जगती, अनुष्टुप् पंक्ति, बृहती, उष्णिक् ये तीन आवृत्तियों से युक्त छन्द प्रतिपादित किये गये हैं।

(गायत्री की चौबीस शक्तियों का वर्णन) प्रहलादिनी, प्रजा, विश्वभद्रा, विलासिनी, प्रभा, शान्ता, मा, कान्ति, स्पर्शा, दुर्गा, सरस्वती, विरूपा, विशालाक्षी, शालिनी, व्यापिनी, विमला, तमोपहारिणी, सूक्ष्मावयवा पद्मालया, विरजा, विश्वरूपा, भद्रा, कृपा और सर्वतोमुखी। अब गायत्री के प्रत्येक अक्षर के अलग-अलग चौबीस तत्त्वों का वर्णन करते हैं- पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, वाक, पैर, पायु- उपस्थ (मल-मूत्रेन्द्रियाँ), त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं ज्ञान यही गायत्री के प्रत्येक अक्षर के चौबीस तत्त्व हैं।

(अब गायत्री के चौबीस अक्षर के अलग-अलग पुष्पों का वर्णन) चम्पा, अलसी (एक नीला फूल), कुंकुम लिइन्द्रनील अग्निप्रभा उत्सूर्य, विशुत्तारक सरोज, गौर, मरकत शुक्ल, कुन्द इन्दु, शंख, पाण्डु-नेत्र, नीलकमल, चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, गोरोचन, मल्लिका, केतकी, कर्पूर के समान इन प्रत्येक अक्षरों के प्रत्येक पुष्पों को याद करना चाहिए।

क्रमश:...

शिवाजी को छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने वाली राजमाता जीजाबाई

अभिनय आकाश

सृष्टि के आदि से लेकर अब तक न जाने कितनी दफा नारी शक्ति का चमत्कार देखने को मिला है। जब-जब अधर्म ने धर्म को, अन्याय ने न्याय को और असत्य ने सत्य को पराभूत करने का प्रयत्न किया। तब-तब ही नारी शक्ति ने आगे बढ़कर धर्म, न्याय और सत्य की रक्षा की है। शिवाजी जिन्हें हम छत्रपति शिवाजी कहकर सम्मान देते हैं। जिन्हें हम एक महान योद्धा और मराठा साम्राज्य के पहले राजा के तौर पर जानते हैं। स्वराज के लिए लड़ने वाले आज भी महाराज को भगवान की तरह पूजते हैं। उनके किस्से आज भी बड़े गर्व से सुने और सुनाए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच हम उस महिला को भूल जाते हैं जिन्होंने शिवाजी को छत्रपति शिवाजी महाराज बनाया। आज आपको वीर शिवाजी की माता जीजाबाई के बारे में बताते हैं।

जिन्होंने अपने बेटे शिवाजी के राज्य में रानी रीजेंट के रूप में अपनी सेवा दी। जिसके लिए उन्हें आमतौर पर राजमाता जीजाबाई के नाम से भी जाना जाता है। हिंद स्वराज की ऐसी योद्धा जो मुगल साम्राज्य के खिलाफ खड़ी रहने वाली देश की सबसे प्रेरणादायक ऐतिहासिक शख्सियतों में से एक हैं। बात 16वीं सदी के आखिर की है तब भारत वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा आज है। 12 जनवरी 1598 को लाखो जी नामक एक नामी सरदार के घर एक बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम जीजाबाई रखा गया। काफी कम उम्र में ही उनकी शादी मालोजी शिलेदार के पुत्र साहजी भोंसले से करवा दी गई। उनके पति ने भी निजाम शाह की सेवा की। उनके आठ बच्चे थे, जिनमें छह बेटियां और दो बेटे शामिल थे। उनमें से एक थे शिवाजी।

जीजाबाई की देशभर्ति और उनके शौर्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। उन्होंने शिवाजी को स्वराज्य की शिक्षा दी और उन्हें एक महान योद्धा के रूप में पाला। शिवाजी जब 14 वर्ष के थे, तब शाहजी राजे ने उन्हें पुणे की जागीर सौंप दी। बेशक, जागीर के प्रबंधन की जिम्मेदारी जीजाबाई पर आ गई। जीजाबाई और शिवाजी कुशल अधिकारियों के साथ पुणे पहुंचे। निजामशाह, आदिलशाह और मुगलों की वजह से पुणे की स्थिति बेहद खराब हो गयी थी। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने दादोजी कोंडादेव के साथ मिलकर पुणे शहर का पुनर्विकास किया। जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत की कहानियाँ सुनाईं। सीता का हरण करने वाले रावण को मारने वाले राम कितने पराक्रमी थे, बकासुर का वध करने वाले और वाले भीम कितने पराक्रमी थे। जीजाबाई ने शिवजी को न केवल कहानी सुनाई बल्कि कुर्सी के बगल में बैठकर राजनीति का पहला पाठ भी सिखाया।

जीजाबाई एक कुशल घुड़सवारी भी थी और कुशलता से तलवार चलाने में भी निपुण थी। उन्होंने कस्बा गणपति मंदिर की स्थापना की। उन्होंने केवरेश्वर मंदिर और तांबाडी जोगेश्वरी मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया। 17 जून 1674 को जीजाबाई की मृत्यु हो गई।

लोकसभा चुनाव के रथ में सवार दलों की सत्ताकांक्षा

ललित गर्ग

विपक्षी दल येन-केन-प्रकारेण भाजपा को सत्ता से बाहर करने में जुटे हैं, इसके लिये विपक्षी दलों में एकजुटता के प्रयास हो रहे हैं। भाजपा एवं उसके सहयोगी दल भी अपनी स्थिति को मजबूती देते हुए पुन: सत्ता में आने के तमाम प्रयास कर रहे हैं।

आजादी के अमृतकाल के पहले लोकसभा चुनाव की आहट अब साफ-साफ सुनाई दे रही है। भारत के सभी राजनीतिक दल अब पूरी तरह चुनावी मुद्रा में आ गये हैं और प्रत्येक प्रमुख राजनैतिक दल इसी के अनुरूप बिछ रही चुनावी बिसात में अपनी गोटियां सजाने में लगे दिखाई पड़ने लगे हैं। 2024 लोकसभा एवं इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, वह पहली बार देखने को मिल रहा है की चुनाव के इतने लम्बे समय पूर्व ही चुनाव जैसी तैयारियां होती हुई दिख रही है। टुकड़े-टुकड़े बिखरे कुछ दल फेवीकॉल लगाकर एक हो रहे हैं। विरोधी विचारधारा के दलों के साथ ग्रुप फोटो खिंचा रहे हैं। सत्ता तक पहुँचने के लिए कुछ दल परिवर्तन को आकर्षण व आवश्यकता बता रहे हैं। कुछ प्रमुख दलों के नेता स्वयं को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देख रहे हैं। मतदाता जहां ज्यादा जागरूक हुआ है, वहां राजनीतिज्ञ भी ज्यादा समझदार एवं चालाक हुए हैं। उन्होंने जिस प्रकार चुनावी शतरंज पर काले-सफेद मोहरें बिछाने शुरु कर दिये हैं, उससे मतदाता भी उलझा हुआ प्रतीत करेगा। अपने हित की पात्रता नहीं मिल रही है। कौन ले जाएगा देश की डेढ़ अरब जनता को आजादी के अमृतकाल में। सभी नंगे खड़े हैं, मतदाता किसको कपड़े पहनाएगा, यह एक दिन के राजा पर निर्भर करता है। सभी इस एक दिन के राजा को लुभाने में जुटे हैं। कोई मुफ्तखोरी की राजनीति का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश करने में जुटा है तो कोई गठबंधन को आधार बनाकर चुनाव जीतने के सपने देख रहा है।

विपक्षी दल येन-केन-प्रकारेण भाजपा को सत्ता से बाहर करने में जुटे हैं, इसके लिये विपक्षी दलों में एकजुटता के प्रयास हो रहे हैं। भाजपा एवं उसके सहयोगी दल भी अपनी स्थिति को मजबूती देते हुए पुन: सत्ता में आने के तमाम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिये एनडीए ने भी नए साथियों की तलाश तेज कर दी है। केंद्रीय गृहमंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की हाल में हुई तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की यात्रा से इसके पक्के संकेत मिले। भाजपा लंबे समय से दक्षिण भारत में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी उसने इस सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर भारत में वह पिछले लोकसभा चुनाव में जितना चमत्कारी प्रदर्शन किया गया कि इस बार उसे दोहराना उसके लिये जटिल प्रतीत हो रहा है। इसलिए अगर उसे फिर से बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में आना है तो दक्षिण में सीटें बढ़ानी होंगी। इससे उत्तर भारत में सीटों की संख्या में संभावित कमी की भरपाई हो जाएगी। भाजपा इस योजना पर पूर्ण आत्मविश्वास एवं प्रखरता के साथ बढ़ भी रही थी, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनावों से उसे झटका लगा। इसके बाद से कहा जा रहा है कि भाजपा पहले जितनी ताकतवर नहीं रही। लेकिन भाजपा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह अपनी हार के कारणों को बड़ी गहराई से लेते हुए उन कारणों को समझने एवं हार को जीत में बदलने के गणित को बिठाने में माहिर है।

आम चुनाव की सरगर्मियां उग्रता पर है, इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प एवं चुनौतीपूर्ण होने वाला है। कांग्रेस ने कर्नाटक की जीत को आम चुनाव की जीत से जोड़ने की जल्दबाजी दिखाना शुरु कर दिया है। जिस तरह हिमाचल एवं कर्नाटक में उसने मुफ्तखोरी की राजनीति का सहारा लिया, उसे वह इसी वर्ष होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा एवं वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में दोहराने को तत्पर है। इसका ताजा प्रमाण है जबलपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की यह घोषणा कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनी तो सौ यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, रसोई गैस सिलेंडर पांच सौ रुपये में दिया जाएगा और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी वादा किया। उन्होंने इसे पांच गारंटी की संज्ञा दी। कुछ इसी तरह की गारंटियां कर्नाटक एवं हिमाचल में दी गयी थी, उन्हें पूरा करने के लिए दोनों ही प्रांतों की चुनी सरकारों को एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य की वित्तीय स्थिति उन्हें पूरा करने की अनुमति नहीं देती। जैसी गारंटियां, लोकलुभावन वादे एवं मुक्त की रेवड़ियां कांग्रेस देने की बात कर रही है, वैसी ही अन्य दल भी कर रहे हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी का सर्वे-सर्वा है। क्योंकि अभी हाल में दिल्ली नगर निगम चुनाव में उसने दस गारंटियां दी थीं। ये गारंटियां और कुछ नहीं लोकलुभावन वादे ही होते हैं, जिन्हें जनकल्याण का नाम दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से छह महीने पहले ही लोक कल्याणकारी योजनाओं की झड़ी लगा रखी है जिससे राज्य का चुनावी माहौल और गर्मा रहा है।

किसी भी राष्ट्र के जीवन में चुनाव सबसे महत्त्वपूर्ण घटना होती है। यह एक यज्ञ होता है। लोकतंत्र प्रणाली का सबसे मजबूत पैर होता है। राष्ट्र के प्रत्येक वयस्क के संविधान प्रदत्त पवित्र मताधिकार प्रयोग का एक दिन। सत्ता के सिंहासन पर अब कोई राजपुरोहित या राजगुरु नहीं बैठता अपितु जनता अपने हाथों से तिलक लगाकर नायक चुनती है। लेकिन जनता तिलक किसको लगाये, इसके लिये सब तरह के साम-दाम-दंड अपनाये जा रहे हैं। हर राजनीतिक दल अपने लोकलुभावन वायदों एवं घोषणाओं को ही गीता का सार व नीम की पत्ती बता रहे हैं, जो सब समस्याएं मिटा देगी तथा सब रोगों की दवा है। लेकिन ऐसा होता तो आजादी के अमृतकाल तक पहुंच जाने के बाद भी देश गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्याओं से नहीं जुझता दिखाई देता। ऐसी स्थिति में मतदाता अगर बिना विवेक के आंख मूंदकर मत देगा तो परिणाम उस उक्ति को चरितार्थ करेगा कि अगर अंधा अंधे को नेतृत्व देगा तो दोनों खाई में गिरेंगे।%%

लोकसभा चुनाव केवल दलों के भाग्य का ही निर्णय नहीं करेगा, बल्कि उद्योग, व्यापार, रक्षा आदि राष्ट्रीय नीतियों, राष्ट्रीय एकता, स्व-संस्कृति, स्व-पहचान तथा राष्ट्र की पूरी जीवन शैली व भाईचारे की संस्कृति को प्रभावित करेगा। वैसे तो हर चुनाव में वर्ग जाति का आधार रहता है, पर इस बार वर्ग, जाति, धर्म व क्षेत्रीयता व्यापक रूप से उभर कर आती हुई दिखाई दे रही है। और दलों के आधार पर गठबंधन भी एक प्रदेश में और दूसरे प्रदेश में बदले हुए हैं। एक प्रांत में सहयोगी वही दूसरे प्रांत में विरोधी है। कुर्सी ने सिद्धांत और स्वार्थ के बीच की भेद-रेखा को मिटा दिया गया है। चुनावों का नतीजा अभी लोगों के दिमागों में है। मतपेटियां क्या राज खोलेंगी, यह समय के गर्भ में है। पर एक संदेश इस चुनाव से मिलेगा कि अधिकार प्राप्त एक ही व्यक्ति अगर ठान ले तो अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी आदि समस्याओं पर नकेल डाली जा सकती है। लेकिन देश बनाने एवं विकास की ओर अग्रसर करने की बजाय सभी दल मुक्त रेवडियां बांट कर एक अकर्मण्य पीढ़ी को गढ़ने की कुचेष्टा कर रहे हैं।

बापू की दिनचर्या

दिन का भोजन (भाग-6)

गतांक से आगे...

उनकी दृष्टि में मन की गुलामी से बढ़कर दूसरा अधम पाप नहीं। महादेव भाई देसाई का यह कथन महत्त्व का है कि बापू के सारे चरित्र की कुंजी इसमें है। श्रेय और प्रेय का अभेद उन्होंने मुद्दत से साध रखा था और श्रेय ही प्रेय है, इस सूत्र को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। मिर्च-मसालों के संबंध में बापू की धारणा थी कि वे स्वादिष्ट नहीं होते, बल्कि वास्तविकता यह है कि चिरकाल से हम उनको खाते रहने के अभ्यस्त हो गए हैं और इसीलिए हमें उनकी गंध और उनका स्वाद प्रिय लगता है। उनके सेवन से हानि के सिवा लाभ नहीं। भारतवासियों की इस प्रवृत्ति की वे कड़ी आलोचना करते। कृत्रिम स्वाद और मिर्च-मसालों के सहारे अधिक आहार करने की आदत छोड़ने पर वे बराबर जोर देते। उदर की अग्नि को उत्तेजित करनेवाले मिर्च, धनिया, जीरा सरीखे मसालों के सेवन से आहार का पाचन तथा उत्तम रक्त-निर्माण की कल्पना को वे कोरी कल्पना बताते। कहते कि इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति उदर रोग, विशेषकर संग्रहणी के शिकार हो जाते हैं। कोचरब-आश्रम में लाल, हरी या सूखी मिर्च के स्थान पर मूली की फली (मोगरी) का उपयोग होता। बापू का कहना था कि वह स्वाद में तीखी होती है। पकाने के बाद उसकी तीक्ष्णता समाप्त हो जाती है, जबकि मिर्च में यह बात नहीं। इस कारण वे उसे पेट के लिए उत्तेजक नहीं मानते। गुजरात में सामान्यत: और विशेषकर अहमदाबाद में मोगरी एक विशिष्ट सब्जी मानी जाती है, जो कच्ची खाई जाती या उसका रायता बनता है। तेल में छौंककर भी उसे बनाते हैं। कोचरब में मिर्च-मसाले की जगह कागजी नींबू दिया जाता। कच्ची मूली-कच्ची मोगरी का उपयोग वस्तुत: महँगे फलों के स्थान पर किया जाता। वैसे, पकाई हुई मोगरी गुजरात (सौराष्ट्र) में जनसाधारण के भोजन का सामान्य अंश होता है। माँड़ निकाले हुए नि:सत्त्व और एक-एक दाना अलग दीखनेवाले चावल के सेवन का भी बापू विरोध करते। मिल का पालिश किया हुआ चावल इस्तेमाल करने और उसे पकाने से पूर्व कई बार धोने के वे विरुद्ध थे। आश्रम में हाथ-कुटे चावल का खूब पका, बिना माँड़ निकाला और हलुए-जैसा भात बनता। चावल पकाने से पूर्व कम धोया और पानी में कुछ समय रख छोड़ा जाता। पकाते समय यह ध्यान रखा जाता कि उसका सारा पानी और माँड़ उसी में समा जाए।

क्रमश: ...

संक्षिप्त समाचार

जो जहां पर हैं, वहीं से हिंदू राष्ट्र बनाने का लें संकल्पः अनिता शर्मा

रायपुर। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज के 81वें प्राक्ट्य दिवस पर रायपुर के रावांभांठा में धर्मसभा का आयोजन किया गया है। इस दौरान धरसींवा विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मंच से कहा कि जो जहां पर है, जिस जगह में हैं, जिस गांव में हैं। वहीं से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लें। हिंदू हित में बात करें। उन्होंने कहा कि हम हिंदू एक रहें, तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। वहीं धर्मसभा के दौरान तीन परिवारों ने धर्म वापसी भी की है। धर्म सभा के शुरू करने से पहले कलश यात्रा निकाली गई, जो बंजारी माता मंदिर से निकाली गई और धर्मसभा पहुंचकर खत्म हुई। इसमें ग्यारह हजार महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। वहीं लोग देशभक्ति के नारे जोर-शोर से लगा रहे हैं। पूरा पंडाल 'हम भारत भव्य बनाएंगे', 'हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे' के नारों से गूंजा उठा।

गेहूं स्टॉक निर्धारण के लिये खाद्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को लिखा पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गेहूं का स्टॉक लिमिट का निर्धारण कर दिया गया है। इस आशय का पत्र मंत्रालय महानदी भवन से 15 जून को प्रदेश के सभी कलेक्टरों को जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 12 जून 2023 को राजपत्र में प्रकाशित कर गेहूं के लिए स्टॉक लिमिट का निर्धारण करने का आदेश दिया गया था। खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि व्यापारी-थोक विक्रेता के लिए 3000 टन का स्टॉक लिमिट तय किया गया है। इसी प्रकार रिटेलर (प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन), बिग चेन रिटेलर (प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन) और उनके सभी डिपो पर 3000 टन स्टॉक लिमिट का निर्धारण किया गया है। इसी तरह प्रोसेसर्स (वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो) स्टॉक लिमिट का निर्धारण किया गया है।

घरघोडा ब्लॉक के कई भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल

रायपुर। रायगढ़ जिले के घरघोडा ब्लाक में कांग्रेस के दिग्गज नेता विभाष सिंह ठाकुर के प्रयासों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार्यशैली से प्रभावित होकर भाजपा पार्षद नीरज शर्मा सरपंच संघ घरघोड़ा अध्यक्ष, जिला गोंड समाज के जिला कार्यकारी अध्यक्ष भूपदेव सिदार,बड़े गुमड़ा से जनपद सदस्य क्रांति गुप्ता ने प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी चंदन यादव, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम व विधायक लालजीत सिंह राठिया के मार्गदर्शन में राजीव भवन रायपुर में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री रवि घोष के समक्ष कांग्रेस प्रवेश किया। प्रदेश महामंत्री द्वारा विधिवत कांग्रेस गमछा पहना कर व सदस्यता रसीद काट कर कांग्रेश प्रवेश कराया। कांग्रेस प्रवेश के पश्चात प्रदेश कांग्रेस के सहप्रभारी चंदन यादव से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया , सभी दिग्गज नेताओं के कांग्रेस प्रवेश से निसंदेह कांग्रेस को मजबूती मिलेगी धरमजयगढ़ विधानसभा में भविष्य में इसका लाभ भी मिलेगा।

जिला स्तरीय सर्तकता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक 20 को

बिलासपुर। जिला स्तरीय सर्तकता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक कलेक्टर श्री सौरभ कुमार की अध्यक्षता में 20 जून को टीएल बैठक के पश्चात मंथन सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2023-24 में दर्ज प्रकरणों के निराकरण स्थिति एवं अधिनियम के तहत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों पर चर्चा की जाएगी।

नगर निगम कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित

बिलासपुर। शहर में वर्षा ऋतु के दौरान पानी निकासी की समस्या का निदान करने एवं अरपा नदी में आने वाली संभावित बाढ़ से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम द्वारा नगर निगम कार्यालय विकास भवन में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07752-471224 है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में 24 घंटे सेवा देने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

बोर्ड की कापियों को जांचने में लापरवाही बरतने वाले 56 शिक्षक ब्लैक लिस्टेड

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकंडरी की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में लापरवाही बरतने वाले 56 शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मंडल ने एक साथ 56 शिक्षकों को ब्लैक लिस्टेड किया है। जबकि 5 शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकने की सिफारिश की है। खबरों के अनुसार बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में लापरवाही बरतने वाले 53 शिक्षकों को अब तीन साल तक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच नहीं कर सकेंगे जबकि तीन शिक्षकों को हमेशा के लिए मूल्यांकन के काम से बाहर कर दिया गया है। मंडल के अनुसार हायर सेकंडरी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों ने गंभीर लापरवाही बरती। जिससे परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम प्रभावित हुए। इस वजह से उनपर कार्रवाई की गई है।

खाद-बीज के अमानक नमूनों के लॉट के विक्रय पर प्रतिबंध

राज्य में खाद, बीज और पौध संरक्षण औषधियों की गुणवत्ता की जांच का अभियान जारी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने खरीफ सीजन के मद्देनजर किसानों को उनकी डिमांड के अनुरूप मानक स्तर के खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खरीफ सीजन की शुरूआत हो चुकी है। किसानों को बेहतर क्वालिटी का खाद और बीज समय मिले, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी तरह की कमी अथवा लापरवाही नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में राज्य के किसानों को मानक स्तर का खाद-बीज और पौध संरक्षण औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा विक्रेता संस्थानों से सेम्पल लिए जाने का अभियान तेजी से शुरू कर दिया गया है। कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अपने-अपने इलाकों में बीज, खाद और कीटनाशक औषधियों के सेम्पल ले रहे हैं, जिसकी जांच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में की जा रही है। खरीफ सीजन 2023 में अब तक बीज के 1712, रासायनिक उर्वरकों के 698 तथा पौध संरक्षण औषधियों के 84 सेम्पल एकत्र कर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच के लिए गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को भेजा जा चुका है।

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुण नियंत्रण प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में बीज के 16, उर्वरक के 14 और पौध संरक्षण औषधि के 3 सेम्पल अमानक पाए गए हैं। अमानक पाए गए सेम्पल के लाट की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने के साथ ही संबंधित फर्मों के संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है। खरीफ फसलों के बीज के अब तक 1712 सेम्पल लिए गए है, जिसमें से 1518 सेम्पल के विश्लेषण में 1502 सेम्पल मानक स्तर के और 16 अमानक स्तर के पाए गए हैं। अभी 194 सेम्पल की प्रयोगशाला जांच प्रक्रियाधीन है। इसी तरह उर्वरकों के लिए गए 698 सेम्पल को प्रयोगशाला में भेजकर जांच कराने का 422 सेम्पल मानक स्तर के तथा 14 अमानक स्तर के पाए गए हैं। उर्वरकों के 219 सेम्पल की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जबकि 43 सेम्पल कतिपय कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं। पौध संरक्षण औषधि के संग्रहित 84 सेम्पल में से 30 सेम्पल मानक स्तर के, 3 अमानक स्तर के पाए गए हैं तथा 37 सेम्पल की जांच अभी प्रक्रियाधीन है। कतिपय कमियों के चलते पौध संरक्षण औषधि के 14 सेम्पल निरस्त कर दिए गए हैं।

सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल से किसान खाद-बीज के लिए लगा रहे चक्कर

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल किसानों के लिए मुसीबत बन रही है। किसान खाद बीज के लिए सहकारी समितियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं जबकि समिति संचालक अपनी मांगों की पूर्ति के लिए अड़े हुए हैं। वहीं, प्रशासन ने अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई है, जिसके चलते किसान लगातार परेशान हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश करने में अब कुछ ही दिनों की देरी है। किसानों ने मानसून के पहले ही खेती किसानी की तैयारियां पूरी कर ली है। अब सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से उन्नत किस्म के बीजों की खरीदी कर खेतों मे व्यवस्थित करना है। कुछ ही दिनों का समय बाकी है तो दूसरी ओर सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। जिस वजह से किसानों को खाद-बीज के लिए सहकारी समिति के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है।

सरगुजा संभाग की समीक्षा बैठक में सचिव डीडी सिंह ने दिये कई निर्देश

■ वन अधिकार पत्र वितरण, देवगुड़ी विकास, छात्रावास-आश्रम के मरम्मत कार्य प्रमुखता से करें

रायपुर। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव श्री डी.डी.सिंह ने कहा है कि प्रदेश में गठित प्रत्येक वन अधिकार समितियों में कम से कम एक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र दिया जाए। विशेष पिछड़ी कमजोर जनजातियों के वन अधिकार पट्टेधारियों को सभी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। वन अधिकार हितग्राहियों को मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों एवं अन्य अनुषंगिक कार्यों में प्राथमिकता दी जाए। श्री सिंह यहां आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में सरगुजा संभाग के सहायक आयुक्तों और परियोजना प्रशासकों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

श्री डी.डी. सिंह ने कहा कि शासन की प्राथमिकता की योजनाएं वन अधिकार मान्यता पत्र, देवगुड़ी विकास, छात्रावास-आश्रम, विभाग द्वारा संचालित एकलव्य एवं प्रयास आवासीय विद्यालय तथा क्रीडा परिसर पर विशेष ध्यान दिया जाए। देवगुड़ी निर्माण, मरम्मत तथा छात्रावास एवं आश्रमों के उन्नयन के कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के दिन वितरित होने वाले वन अधिकार के पात्र हितग्राहियों का चयन कर सूची तैयार कर ली

जाए। छात्रावास-आश्रमों में निर्माण कार्यों को सत्र प्रारंभ होने के पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाए। सहायक आयुक्त एवं परियोजना प्रशासक निर्माण कार्यों के गुणवत्ता की जांच स्थल पर जाकर करें। उन्होंने कहा कि छात्रावास-आश्रमों में साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दें। छात्रावास-आश्रमों को आदर्श रूप में विकसित करे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के द्वितीय चरण में चयनित गांव में सर्वे कराकर वहां के विकास के लिए कार्ययोजना तैयार करें।

आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत जहां विशेष पिछड़ी कमजोर जनजातियों को अधिक वन अधिकार पट्टे दिए गए हैं, उन्हें आदर्श गांव घोषित करें और इन हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाए। उन्होंने नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन एवं वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले आदर्श ग्राम के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। श्रीमती आबिदी ने कहा कि विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के लिए आवास भी बनाए जाने है, इसके लिए इन वर्गो के मुखिया और हितग्राहियों से चर्चा कर उनके संस्कृति के अनुरूप घर बनाया जाए। आवास का निर्माण वैध जमीन पर ही किया जाए और वहां बिजली, पानी की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए मेस संचालन, खेल सामग्री क्रय करने की कार्रवाई नियमानुसार शीघ्र पूर्ण कर ली जाए।

जिले के सहायक आयुक्त इसके लिए इन स्कूलों का अकादमी कैलेण्डर तैयार कर उसका पालन सुनिश्चित करवाए। इन स्कूलों के शिक्षकों को विषय-वस्तु के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए। इन स्कूलों के बच्चों का प्रत्येक माह यूनिट टेस्ट लेकर बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों का आकलन करें। विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित क्रीड़ा परिसरों में स्वीकृत लघु निर्माण कार्यों का मौके पर मुआयना कर इन कार्यों को शीघ्र ही पूरा करवाए। क्रीडा परिसरों में बच्चों की समय पर भर्ती हो। इन क्रीडा परिसरों में खेल विधाओं के अनुसार कैम्प लगाकर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए।

हेल्थ एक्सपो का स्वास्थ्य मंत्री ने किया अवलोकन, मशीनों का डेमो भी देखा

रायपुर। मेडिकल एवं लैब उपकरणों की खासियतों की ली जानकारी, मशीनों का डेमो भी देखासभी स्टॉलों में जाकर मेनुफेक्चरर्स, सप्लायरों और सेवा प्रदाताओं से की चर्चा, मशीनों का डेमो भी देखा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित हेल्थ एक्सपो का अवलोकन किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इंडियन मेडिकल एशोसिएशन, इंडियन डेंटल एशोसिएशन और एशोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स - इंडिया के छत्तीसगढ़ चैप्टर के सहयोग से इस तीन दिवसीय एक्सपो का आयोजन किया गया है।

14 जून से 16 जून तक चलने वाली इस एक्सपो में मेडिकल उपकरण, लैब उपकरण, मेडिकल फर्नीचर, मेडिकल क्लोदिंग तथा कन्युमेबल्स बनाने और इनकी आपूर्ति करने वाली देश-विदेश की नामी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन एवं अन्य सेवा प्रदाता कंपनियों ने भी यहां अपने स्टाल लगाएं हैं। प्रदेश के कई बड़े अस्पतालों और निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ ही अनेक जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा भी यहां स्टॉल लगाए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने हेल्थ एक्सपो के अवलोकन के दौरान यहां प्रदर्शित मेडिकल एवं लैब उपकरणों के उपयोग, कीमत और खासियतों की

जानकारी ली। उन्होंने मशीनों का डेमो भी देखा। श्री सिंहदेव ने सभी स्टॉलों में जाकर मेनुफेक्चरर्स, सप्लायरों और सेवा प्रदाता कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा भी की। उन्होंने एक्सपो में भाग लेने वाली सभी कंपनियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि यहां एक छत के नीचे अलग-अलग तरह के मेडिकल उपकरणों और मशीनों के बारे में जानकारी मिल रही है। अस्पतालों में उपयोग होने वाली अलग-अलग कंपनियों के उपकरणों का डेमो भी यहां देखा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने एक्सपो में भाग ले रही कंपनियों से कहा कि प्रदेश में मेडिकल उपकरणों, कन्युमेबल्स और दवाईयों की आपूर्ति के लिए मेनुफेक्चरर व सप्लायर फ्रेंडली व्यवस्था बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इससे इनकी आपूर्ति में तेजी आने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़े वेंडर्स को भी सहुलियतें होंगी। श्री सिंहदेव के हेल्थ एक्सपो के भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त डॉ. सी.आर. प्रसन्ना और इंडियन मेडिकल एशोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता भी साथ थे।

राज्य के 36 गढ़ कल्चुरी काल के मुख्य प्रशासनिक यूनिटः संभागायुक्त अलंग

रायपुर । रायपुर संभागायुक्त संजय अलंग आज एनआईटी में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित युवा संगम कार्यकम में शामिल हुए। उन्होने नागालैंड के एनआईटी सहित विभिन्न शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक-ऐतिहासिक विरासत से परिचित कराते हुए छत्तीसगढ़ के नाम की व्याख्या की। श्री अलंग ने बताया कि छत्तीसगढ का इतिहास गौरवशाली रहा है। यहां कल्चुरी वंश के त्रिपुरी शाखा का आधिपत्य रहा हैं। उन्होने पहले तुम्माण उसके बाद रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। उस समय छत्तीसगढ़ दक्षिणी कोसल के नाम से जाना जाता था, जो कि छोटी-छोटी जमीदारियों में बंटा हुआ था। इसे उन्होंने मांडलिक नाम दिया।

श्री अलंग ने बताया कि कल्चुरी राजाओं ने प्रशासनिक सुव्यवस्था

स्थापित करने के लिए अपने आधिपत्य वाले क्षेत्र को विभिन्न प्रशासनिक यूनिट में बांटा जिसे ही गढ़ का नाम दिया जो छत्तीसगढ़ के नाम से प्रचलन में आया। कालान्तर में अंग्रेजों ने इसे तहसील का नाम दिया जो आज भी प्रशासनिक इकाई मानी जाती है। शिवाजी का उल्लेख करते हुए श्री अलंग ने मराठा साम्राज्य के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ में कल्चुरियों के बाद भोसले शासक ने शासन किया। मराठा शासको ने अपने सैनिकों को राजस्व वसूली का कार्य दिया। उनके राजस्व का प्रमुख स्रोत टैक्स थे। जिसे सरदेशमुखी और चौथ कहा जाता था। इनके सैन्य अधिकारी जो राजस्व वसूली कर लाते थे। उन्हे मराठा राजाओं के अधिकारी फडवनीस और चिटनीस रिकार्ड रखते थे। संबधित क्षेत्रों से राजस्व वसूली के संगहण के रिकार्ड रखने के दौरन ही शनैःशनैः छत्तीसगढ शब्द प्रचलन में आता गया। श्री अलंग ने नागपुर शहर के संस्थापक बख्तबुलंद तथा मवाल समाज के संबंध में रोचक जानकारी शेयर की। उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं को समकालीन समय का उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे की आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसमें माहिष्मती का जिक्र आता है। संयोग यह है कि कोसल से जुडे ऐतिहासिक वृतांतों में इसके अनेक वर्णन मिलते है। यद्यपि फिल्म में यह काल्पनिक कहानी है।

पटवारियों की हड़ताल खत्म

■ सीएम भूपेश बघेल से की मुलाकात, जनहित में हुआ फैसला

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म हो गई है। पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी है। बीते दिनों हड़ताल खत्म करने के बाद सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। इसमें जनहित में फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि हड़ताल से आम जनता, किसान और छात्रों का काम ठप पड़ा था।

पटवारी संघ 15 मई से हड़ताल पर थे। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से आम जनता को राजस्व संबंधी कार्यों में दिक्कत हो रही थी। राजस्व विभाग से जुड़ी जरूरी काम भी ठप पड़ा था। इससे राज्य सरकार ने पटवारियों के कार्य करने से इंकार किए जाने का एस्मा भी लगाया था। जिसका संघ ने और बीजेपी ने कड़ा विरोध किया था। एस्मा लगाने के बाद भी पटवारी हड़ताल पर टिके हुए थे।

पटवारियों की इस हड़ताल से किसान वर्ग, आम जनता, युवा वर्ग, विद्यार्थी और राजस्व संबंधी कार्य रुका हुआ था। इस समय शिक्षा सत्र चालू होने और रिक्त पदों की भर्ती के लिए विद्यार्थियों को जाति,

निवास, आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। ये जरूरत की कागजात नहीं बन रहा था। वहीं किसानों वर्गों को भी काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब लोगों की समस्याओं को देखते हुए पटवारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है।

इस अवसर पर प्रदेश राजस्व पटवारी संघ के अध्यक्ष भागवत कश्यप, कार्यकारी अध्यक्ष ज्योति सर्वे, कोषाअध्यक्ष सतीश चन्द्राकर, सह-सचिव बृजेश राजपूत, रायपुर जिला अध्यक्ष कमलेश तिवारी, संरक्षक संतोष त्रिपाठी, प्रदेश सह सचिव मुरली वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता विरेन्द्र बैस, सुदर्शन पनका और नीरज सिंह उपस्थित थे।

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने दी अगले माह से हड़ताल पर जाने की चेतावनी

रायपुर। पटवारियों की हड़ताल माह भर खत्म हुई तो अब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अगले माह से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। लंबित मांग पूरी नहीं होने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जुलाई से हड़ताल पर , करेंगे। इसे लेकर संभाग स्तरीय सम्मेलन बिलासपुर में घोषणा की गई।

प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की संभागीय बैठक में बिलासपुर संभागीय अध्यक्ष विकास कुमार यादव व प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा ने संयुक्त बयान जारी करते हुए बताया की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 4 जुलाई से संघ के सदस्य राज्य में अनिश्चित कालीन आंदोलन करेंगे।

संभाग अध्यक्ष यादव ने बताया कि समय-समय पर राज्य के स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर शासन को अवगत कराया गया है तथा समय-समय पर आंदोलन व पत्राचार कर ध्यान आकृष्ट कराया गया परंतु शासन में

इस संबंध में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को वर्षों से केंद्रीय वेतनमान प्रदाय नहीं किया जा रहा है। कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर कोविड महामारी को नियंत्रण करने में सफलता पाई इस दौरान कई कर्मचारी को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। परंतु सरकार द्वारा घोषणा के बाद भी किसी प्रकार की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का वितरण नहीं किया गया।

मेकाज के कर्मचारियों ने काम बंद किया, वार्ड में सेवाएं हुई ठप

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित मेडिकल कालेज में कार्यरत वार्ड बॉय, स्टाफ नर्स से लेकर अन्य विभाग में काम करने वाले डीएमएफडी कर्मचारियों ने शुक्रवार को काम बंद करते हुए अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में आकर प्रदर्शन किया। वहीं, इस मामले को लेकर अधिकारी से भी मिलकर उनसे चर्चा करने के साथ ही साथ जल्द वेतन दिलाने की मांग भी की। वही इन सभी के वार्ड छोड़कर आने से वार्ड के कई महत्वपूर्ण काम आदि बाधित हो गए। जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामले के बारे में जानकारी देते हुए डीएमएफडी संघ के अध्यक्ष रिकेश्वर ने बताया की करीब तीन माह से वेतन नहीं मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, घर खर्च चलाने से लेकर रोजाना 100 रुपए का पेट्रोल खर्च करते हुए ड्यूटी आना पड़ता है। आज-कल करते हुए रोजाना पैसे आने की उम्मीद जताई जाती है, लेकिन वेतन का कोई भी नामों निशान नहीं दिख रहा है। वहीं, कुछ महिला कर्मचारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में बच्चों का स्कूल खुलने वाला है। ऐसे में स्कूल फीस से लेकर कापी किताब, ड्रेस आदि का खर्च किस तरह से वहन किया जाएगा। पहले अस्पताल में बस भी संचालित ती, लेकिन उसे भी बाद में खराबी के चलते बंद कर दिया गया। जब वेतन ही नही मिलेगा तो खर्च कैसे चलाया जाएगा। डीएमएफडी कर्मचारियों ने शुक्रवार को अधीक्षक डॉक्टर अनुरूप साहू से मुलाकात करते हुए वेतन ना मिलने के बारे में बताया, जहां अधीक्षक का कहना है कि इस मामले को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है, जिससे की जल्द से जल्द वेतन मिल सके। अपने वेतन की मांग को लेकर डीएमएफडी कर्मचारियों ने दो घंटे तक वार्ड में काम को बंद करते हुए अधीक्षक के रूम के सामने बैठकर उनका इंतजार किया और आने के बाद उन्हें समस्या से अवगत भी कराया।

कभी हो मुखातिब तो कहूँ, क्या मर्ज़ है मेरा...

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गनाइजर के जरिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ी नसीहत दी है। ऑर्गनाइजर ने अपने संपादीय में लिखा है कि भाजपा को आगे भी चुनाव जीतते रहना है तो सिर्फ मोदी मैजिक और हिंदुत्व का चेहरा काफी नहीं होगा यही

नहीं,इस संपादकीय के जरिए संघ ने कर्नाटक में भाजपा की हार का कारण भी बताया है।अगले साल देश में लोकसभा का चुनाव होना है, इसके पहले 5 राज्यों मे विधानसभा चुनाव भी होने हैं।छत्तीसगढ़,मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान शामिल हैं। मध्य प्रदेश में अभी भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता है। तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। इन चुनावों के पहले संघ के मुखपत्र में छपे इस लेख ने सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संघ ने भाजपा को क्यों ऐसी नसीहत दी....? 2024 चुनाव से पहले इसके सियासी मायने क्या हैं? आरएसएस ने अपने मुखपत्र आर्गनाइजर में एक संपादकीय प्रकाशित किया।इसमें कर्नाटक चुनाव में भाजपा को मिली हार का विश्लेषण किया गया। ये संपादकीय ऑर्गनाइजर में कर्नाटक चुनाव का जिक्र किया गया है।कहा गया है कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद पहली बार भाजपा को विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोपों का बचाव करना पड़ा है। 14 मंत्री चुनाव हार गए। ये चिंता का विषय है।आगे लिखा गया है कि %जब राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की भूमिका न्यूनतम होती है और चुनाव अभियान स्थानीय स्तर पर रखा जाता है तो कांग्रेस को फायदा होता है। परिवार द्वारा संचालित पार्टी ने राज्य स्तर पर एक एकीकृत चेहरा पेश करने की कोशिश की और 2018 के चुनावों की तुलना में पांच प्रतिशत अतिरिक्त वोट हासिल किये।%संपादकीय में लिखा गया है कि केवल पीएम मोदी के चेहरे और हिंदुत्व के बल पर भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती है...? भाजपा को स्थानीय स्तर पर नए नेताओं को आगे लाना होगा। केंद्र से तालमेल बिठाकर काम करना होगा, तभी आगामी चुनावों में भाजपा को जीत मिल सकती है।

तीन दिन जिलों से बाहर रहे कलेक्टर,एसपी....

छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है ज़ब सभी 33 जिलों के कलेक्टर और एसपी जिला मुख्यालय छोड़कर 3 दिनों से राजधानी में मौजूद हैं।छग में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2 दिन 8और 9 जून को बैठक ली जिसमे छग के सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी मौजूद थे, उनसे वन टू वन बातचीत की गई। वहीं 10 जून को 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मेरिट में आए छात्र छात्राओं को राज्य शासन ने हेलीकाप्टर की सैर कराई वहीं उनके सम्मान समारोह में सभी कलेक्टर, एसपी को मौजूद रहने का निर्देश मिला था। इस तरह 3 दिन कलेक्टर और एसपी जिला मुख्यालय से दूर रहे...

जुनेजा ही विस,लोस चुनाव करवाएंगे

अशोक जुनेजा छग में पूर्णकालीन डीजीपी 5 अगस्त 22 को बन गये थे, गृह विभाग ने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि पुलिस बल के प्रमुख पदभार ग्रहण करने के बाद 2 साल तक इस पद पर बने रह सकेंगे। इस हिसाब से इसी माह 30 जून में जुनेजा रिटायर नहीं होंगे क्योंकि छग सरकार फिलहाल उन्हें हटाने के मूड में नहीं है।वे अगस्त 24 में रिटायर होंगे यानि अगला विस तथा लोस चुनाव वहीं करवाएंगे।यूपीएससी की अनुशंसा के बाद अब जुनेजा अगस्त 24 में रिटायर होंगे,पहले वे जून 23 में रिटायर होने वाले थे।इधर विशेष डीजी राजेश मिश्रा जनवरी 24 में रिटायर होंगे इसलिये ये अगले डीजीपी की दौड़ से बाहर ही हो गये हैं?वहीँ अरुण देव गौतम जुलाई 27, पवन देव जुलाई 28, हिमांशु गुप्ता जून 29, जीपी सिंह जून 29 (अभी निलंबित), एसआरपी कल्लूरी मई 31,प्रदीप गुप्ता जुलाई 31, विवेकानंद सिन्हा जनवरी 32, दीपांशु काबरा जुलाई 34 में रिटायर होंगे। इधर प्रतिनियुक्ति पर होनेवाले वरिष्ठ आईपीएस रवि सिन्हा जनवरी 24,स्वागत दास नवम्बर 24, जयदीप जुलाई 30 में रिटायर होंगे तो एडीजी तथा सीबीआई में संयुक्त संचालक पदस्थ अमित कुमार दिसंबर 35 में सेवानिवृत होंगे।

छग के 2आईएएस को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी....

केंद्र सरकार ने प्रशासन में शीर्ष स्तर पर बड़े फेरबदल किए हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमित अग्रवाल और सुबोध कुमार सिंह को नई जिम्मेदारियां दी हैं। अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण /आधार कार्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है, तो सुबोध कुमार सिंह को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डायरेक्टर जनरल का पद दिया गया है।अमित अग्रवाल 1993 बैच के और सिंह 1997 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।

माओवादी आनंद उर्फ सुदर्शन कट्टम की मौत

शीर्ष माओवादी नेता आनंद उर्फ सुदर्शन कट्टम की छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के वन क्षेत्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गयी।उस पर डेढ़ करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। कट्टम 69 वर्ष का था। उसकी मौत 31 मई को हुई। एडीजी (नक्सल ऑपरेशन) विवेकानंद ने कट्टम की मौत की पुष्टि की है। वह माओवादियों की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो सदस्य था। सरकार ने उस पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया था। माओवादियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कट्टम की मौत की जानकारी दी है।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आनंद उर्फ सुदर्शन कट्टम 2011 में दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले का मास्टरमाइंड था। बता दें कि इस नक्सली हमले में 70 जवान शहीद हुए थे। इस हमले को देश के सबसे बड़े नक्सली हमलों में से एक माना जाता है।

रक्षा-सुल्तानऔर सफ़ेद बाघ के 3 शावक...

छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के मैत्री बाग चिड़ियाघर में एक सफेद बाघिन ने 3शावकों को जन्म दिया है। इन तीन बाघ शावकों के जन्म भिलाई के मैत्री बाग

चिड़ियाघर में मौजूद सफेद बाघों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है। चिड़ियाघर के प्रभारी एनके जैन ने बताया कि रक्षा नाम की सफेद बघिन ने शवकों को जन्म दिया,सफेद बाघ सुल्तान इन शावकों का पिता है।पिछले साल सितंबर में रोमा नाम की एक सफेद बाघिन ने एक शावक को जन्म दिया था,जिसका नाम 'सिंघम' रखा गया है। जैन ने कहा कि मौजूदा समय में इस चिड़ियाघर में अप्रैल में जन्मे तीन बाघ शावकों सहित कुल नौ सफेद बाघ हैं। 1997 में सफेद बाघ के एक जोड़े-तरुण और तापसी को पहली बार पड़ोसी राज्य ओडिशा के नंदन-कानन चिड़ियाघर से मैत्री बाग में स्थानांतरित किया गया था।

और अब बस

- छग में भाजपा का 65+ का नारा अमित शाह ने 2018के विस चुनाव में दिया था पर केवल 15 सीट ही आई ... अब कांग्रेस का 2023 के विस चुनाव में 75+ सीटें आने का नारा चर्चा में है....?
- छत्तीसगढ़ कैडर के 2004 बैच के चार आइपीएस अजय यादव, संजीव शुक्ला,नेहा चंपावत और अभिषेक पाठक को केंद्र सरकार द्वारा आईजी इंपैनल किया गया है।
- एसपी की एक छोटी तबादला सूची जल्दी ही आने वाली है?

मैदान में उतरने से पहले ही हार मान गयी कांग्रेसः चंदेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही हार मान चुकी है। इसे अब चुपचाप पैवेलियन लौट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, टी.एस. सिंहदेव के बयान कांग्रेस की अंदरूनी कलह का संकेत तो पहले ही दे चुके थे, अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मान लिया है कि सत्ता में वापसी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। श्री चंदेल ने कहा कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी को लेकर मंत्री सिंहदेव के ताजा बयान के बाद मुख्यमंत्री बघेल का यह कहना कि 'बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं, हम सरकार तो बना लेते हैं लेकिन उसे रिपीट नहीं कर पाते', प्रदेश की अपराध-बोध से ग्रस्त कांग्रेस सरकार की हताशा व निराशा को दर्शाता है।

प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री चंदेल ने कहा कि हजारों करोड़ रुपए के शराब, रेत, जमीन, कोयला, पीडीएस राशन, गरीबों के मुफ्त अनाज में घोटाले करने के बाद, नकली शराब पिलाकर प्रदेश के लाखों परिवार और जन-स्वास्थ्य से क्रूरतम खिलवाड़ करने के बाद, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और 25 हजार अबोध शिशुओं की मौत के बाद, 7 हजार महिलाओं के साथ हुए वहशियाना अनाचार के बाद, साढ़े 3 हजार क्रूर हत्याओं के बाद, 26 हजार किसानों, गरीबों, युवाओं की आत्महत्या के बाद, छत्तीसगढ़ को आकंठ कर्ज में डुबाने के बाद, गंगाजल हाथ में लेकर कसमें खाकर भी वादाखिलाफी के कीर्तिमान रचने के बाद, प्रदेश के संसाधनों की खुलेआम लूट मचाकर छत्तीसगढ़ को अपने 'खानदानी सियासी आकाओं' का एटीएम बना देने के बाद, भगवान राम के ननिहाल में धर्मांतरण और तुष्टीकरण का घातक एजेंडा चलाकर धर्म-संस्कृति को नष्ट करने व हिन्दू समाज का उत्पीड़न करने के बाद और हर मोर्चे पर छत्तीसगढ़ के विकास को बाधित करने बाद राजनीतिक अपराध बोध ने मुख्यमंत्री बघेल को काफी बेचैन कर रखा है और कांग्रेस सरकार व नेताओं की नींद उड़ा रखी है।

अवैध उत्खनन का होना राजनीतिक संरक्षण : चंद्रशेखर साहू

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने कहा है कि अब कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने भी रेत, गिट्टी, मुरुम की खदानों में चल रहे अवैध उत्खनन का मामला

उठाकर प्रदेश सरकार के राजनीतिक संरक्षण में चल रहे माफियाराज की पुष्टि कर दी है। विदित रहे, जिला पंचायत की बैठक में विधायक श्री साहू ने इस अवैध कारोबार को रोकने में विफलता के लिए खनिज अधिकारियों पर भी नाराजगी जताई। इस बैठक में कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा भी मौजूद थे। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के संरक्षण में माफियाओं ने जंगलराज कायम कर रखा है। रेत खदानों से अवैध उत्खनन के सैकड़ों मामले सामने आने के बाद भी इन माफियाओं पर कोई नकेल नहीं कसी जा रही है। रेत माफियाओं ने अवैध उत्खनन की सारी हदें लांघकर कांग्रेस के शासनकाल में शुरू से ही प्रदेश के सभी जिलों में रेत के पहाड़ तक खड़े कर लिए और मनमानी कीमत पर रेत बेचने का काम किया है और आज भी वे बेखौफ अपना अवैध कारोबार चला रहे हैं। अवैध उत्खनन का विरोध करने वालों पर जानलेवा हमले किए गए और हत्याएं तक की गईं, लेकिन प्रदेश की कमीशनखोर सरकार ने कानून-व्यवस्था से कोई सरोकार ही नहीं रखा।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर

■ **राज्य स्तरीय आयोजन में 21 हजार लोगों के योगाभ्यास करने का लक्ष्य**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। योग दिवस पर आयोजित समारोह को सफल बनाने छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा ने आज धरमपुरा स्थित कार्यालय में योग सेंटर संचालकों की विशेष बैठक ली। बैठक में कार्यक्रम की रूप रेखा की कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया गया कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जोरा स्थित कृषि महाविद्यालय के मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस दिन बड़ी संख्या में लोग छत्तीसगढ़ में योगाभ्यास करेंगे। राज्य स्तरीय आयोजन में इस वर्ष 21 हजार लोगों का एक साथ योगाभ्यास करने का लक्ष्य है।

श्री शर्मा ने बताया कि पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम 'एक विश्व एक स्वास्थ्य' रखी गई है। इस दिन योग के माध्यम से 'हर

घर आंगन योग' के संदेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय के प्रमुख स्थलों जैसे- ऐतिहासिक, सार्वजनिक महत्व के स्थल, महत्वपूर्ण नदियों वाले स्थलों पर अधिक से अधिक भागीदारी के साथ सामूहिक योग अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के शहरों और गांवों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चे, वृद्धा आश्रमों में रहने वाले बुजुर्ग सहित कई नव जवान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होकर योगाभ्यास करेंगे। उन्होंने लोगों से योग करने का आग्रह करते हुए कहा कि स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए सभी दैनिक जीवन में योग को अपनाएं।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

नेहरू संग्रहालय का नाम बदलना केंद्र सरकार की संकुचित मानसिकताः मरकाम

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल के नाम पर बने नेहरू संग्रहालय के नाम को बदले जाने को कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी और भाजपा की संकुचित मानसिकता बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने

कहा कि संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। 59 वर्षों से अधिक समय से नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय दुनिया भर के विद्वानों के लिये जिज्ञासा शांत करने का केंद्र रहा है। मोदी सरकार ने इसका नाम बदलकर अपनी छोटी सोच को प्रदर्शित किया है। भाजपा कहां-कहां से महात्मा गांधी और पं. जवाहर लाल नेहरू के नाम को हटायेगी। नेहरू का नाम जो देश के जन मन में रचा बसा है। भाजपा और मोदी दुर्भावनावश पं. जवाहर लाल नेहरू के नाम से बने संग्रहालय का नाम भले ही बदल ले लेकिन पं. नेहरू द्वारा बनाये गये भाखड़ा नांगल बांध सिंचाई परियोजनाये बोकारो, राउर केला, दुर्गापुर, भिलाई जैसे उद्योगो पर से नेहरू जी की छाप कैसे मिटायेंगे? जब भाजपा के पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय, अपने दल के राजनैतिक वजूद की तलाश के लिये देश में हिन्दू मुस्लिम और क्षेत्रवाद का जहर बो कर सांप्रदायिकता फैलाकर विघटन फैलाने की कोशिशे में लगे हुये थे।

कांग्रेस सरकार के 'कैश फॉर जॉब' घोटाले ने प्रदेश को फिर किया शर्मसारः देवलाल

रायपुर। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा है कि तमाम तरह के घोटाले और भ्रष्टाचार से काली कमाई करने के बाद भी प्रदेश कांग्रेस और उसकी राज्य सरकार के लोगों की भूख शांत नहीं हुई है और अब 'कैश फॉर जॉब' घोटाला करके युवाओं के साथ छलावा करने पर आमादा है। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय स्तर पर ईडी-सीडी और घोटालों के गढ़ के रूप में जो पहचान बना दी है, उसके लिए कांग्रेस और उसकी भूपेश सरकार को छत्तीसगढ़ अब कतई माफ नहीं करेगा।भाजपा प्रवक्ता श्री ठाकुर ने कहा कि एक तरफ देश में जहां विकास के नित-नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में घोटालों की बयार बह रही है। श्री ठाकुर ने वनरक्षक पद पर 'सीधी भर्ती' के नाम पर एक अभ्यर्थी से खुलेआम 6 लाख रुपए की मांग करने के सामने आए स्टिंग मामले का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार देने के नाम पर युवाओं के साथ इस तरह की घिनौनी सौदेबाजी पर उतरकर अपने शर्मनाक कृत्य कर रही है। ऐसे अनेक मामले पहले भी सामने आए हैं जिनमें सरकारी नौकरी के बदले बेरोजगार युवाओं से खुलेआम राशि की मांग की जाती रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के नाम पर जिस तरह लूटा जा रहा है, उसकी शायद ही कोई और मिसाल देखने को मिले। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकारी नौकरी के बदले पैसे का खेल, रेट कार्ड का खेल, अब देश से कुछ भी छिपा नहीं है।

शराबबंदी के बदले नशाबंदी की बात धोखामात्र : सरोज

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की सांसद डॉ. सरोज पांडेय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नशाबंदी को लेकर दिए गए बयान पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा है कि 2 हजार करोड़ रुपए

का शराब घोटाला करने के बाद मुख्यमंत्री बघेल अब नशाबंदी की बातें कर रहे हैं। डॉ. पांडेय ने कहा कि गंगाजल हाथ में लेकर पूर्ण शराबबंदी की कसम खाने के बाद भी प्रदेश की भूपेश सरकार ने शराबबंदी का अपना वादा पूरा नहीं किया। इस झूठी सरकार की किसी भी बात पर प्रदेश अब कोई भरोसा नहीं करेगा।नकली, जहरीली और ओवररेट शराब बिक्री के गोरखधंधे के जरिए हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करने वाली प्रदेश सरकार के मुखिया अब 'नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली' की कहावत चरितार्थ कर नशाबंदी की बातें करके प्रदेश को भरमाने में लगे हैं। जिस छत्तीसगढ़ को प्रदेश सरकार के संरक्षण में ड्रग्स, गांजा, अफीम, चरस समेत तमाम मादक पदार्थों की तस्करी और गोरखधंधे का अड्डा बनाकर रख दिया गया है, जहरीली शराब पिला-पिलाकर लोगों की सेहत और जान से खिलवाड़ करने वाली प्रदेश सरकार मादक पदार्थों के जरिए प्रदेश के किशोर से लेकर युवाओं तक के भविष्य को तबाह कर देने के पाप की भी उतनी ही भागीदार है।

सरोज पांडे बताये क्या वो नशाबंदी के खिलाफ हैः धनंजय

रायपुर। भाजपा सांसद सरोज पांडेय के बयान पर पलटवार करते हुये प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा की जब-जब मुख्यमंत्री नशा के खिलाफ कार्यवाही करते है भाजपा के नेता पता नहीं क्यों तिलमिला जाते है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की

सरकार के द्वारा प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए शुरू की जा रही नशाबंदी अभियान से भाजपा को तकलीफ क्यों हो रही है?भाजपा सांसद सरोज पांडेय को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि वो नशाबंदी अभियान के समर्थन में हैं या विरोध में? क्या भाजपा चाहती है कि प्रदेश के युवा नशा के गर्त में डूबे रहे है?प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल के दौरान शराब का सरकारीकरण किया गया प्रदेश भर में हुक्का बार खोलेने का लाइसेंस दिया गया। गांव गांव में अवैध रूप से शराब गांजा भांग नशीली वस्तुओं बिकवाया गया। भाजपा से जुड़े कई लोग नशीली वस्तुओं की तस्करी के मामले में अभी गिरफ्तार हुये हैं इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी नशीली वस्तुओं के तस्करों के साथ सांठगांठ करके युवाओं को नशे के गर्त में धकेलने का षड्यंत्र रच रही है।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां अवैध रूप से नशीली वस्तुओं के कारोबार चरम सीमा पर है नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात के मुद्रा पोर्ट में हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाते हैं।

भाजपा राज में सरकार से लेकर प्रशासन तक थी माफियाओं की पैठः वर्मा

रायपुर। राज्य में माफिया के पनपने के भाजपा नेता चंद्रशेखर साहू के आरोपो का जवाब देते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि राज्य में माफिया के पैठ की शुरुआत

भाजपा के राज में शुरू हुई थी जिस पर भाजपा सरकार के जाते ही लगाम भी लगाया जा चुका है। भाजपा के राज में एक नए किस्म के माफिया का उदय हो गया था जो सत्ता और प्रशासन को हथियार बना कर अपनी दादागिरी को कानून का आवरण डाल कर छुपाये रखता था। रमन राज में प्रत्येक जिले में विशेष सेल और क्राइम ब्रांच बनाकर प्रशासनिक आंतकवाद का गिरोह संचालित किया जाता था। दबावपूर्वक जमीन मकान खाली कराना, जमीन हड़प कर जबरिया कब्जा करना, खनन माफिया को संरक्षण देने का काम रमन सरकार के संरक्षण में होते रहे। रमन सिंह के कुशासन में रेत माफिया नागू चंद्राकर को दिये गये संरक्षण, समोदा घाट में दिन दहाड़े सरपंच की गोली मारकर की गयी हत्या को जनता भूली नहीं। कांग्रेस की सरकार बनते ही सारे माफियाओ का पतन शुरू हो गया है, चाहे प्रशासनिक आतंक फैलाने वाला प्रशासनिक माफिया हो या पुलिस आतंक फैलाने वाला माफिया हो या भाजपा द्वारा पोषित कोल और कबाड़ माफिया हो सभी के हौसले पस्त हो चुके है।

सीएम फेस पर सियासत ▶ **मुख्यमंत्री के बयान पर साव का पलटवार**

बघेल जी अपनी चिंता करें, वे अपनी पार्टी में चेहरा हैं कि नहीं

लोरमी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर लोकसभा के सांसद अरुण साव लोरमी दौरे पर रहे. इस दौरान अरुण साव ने भाजपा के पास ओम माथुर के अलावा कोई चेहरा नहीं होने के वाले ष्टरूबघेल के बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जी अपनी पार्टी की चिंता करें, वे अपनी पार्टी में चेहरा हैं कि नहीं.इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है कि चेहरा होगा या नहीं होगा. साव ने कहा कि कहा बघेल जी ने तो हार स्वीकार कर ही लिया है, नवंबर में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की विदाई तय है.

वहीं अरुण साव ने इस कार्यक्रम में उपस्थित बीजेपी कार्यकर्ताओ को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को टिप्स देते हुए बेहतर कार्य के लिए चार्ज भी किया गया.इसके अलावा कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के धर्मांतरण रद्द करने मामले पर बयान पर कहा कांग्रेस हमेशा ही हिन्दू समाज के साथ अन्याय अत्याचार और तुष्टिकरण की राजनीति की है. धर्मांतरण कानून को रद्द करना इसका परिचायक है, ये राष्ट्रहित में उचित नहीं है.

बता दें कि तेली मोहतरा में आयोजित टिफिन बैठक और वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में शामिल हुए. इस बीच भाजपा पदाधिकारी समेत कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया. इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय भी मौजूद रहे.

धरना प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा-यातायात व्यवस्था के हो पुख्ता इंतजाम : कलेक्टर

रायपुर। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शहर की कानून व्यवस्था से जुडे विषयों पर बैठक ली। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल उपस्थित थे। डॉ भुरे ने आगामी दिनों शहर में होने वाले धरना प्रदर्शन के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख स्थानों में धरना प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाबलों की पर्याप्त संख्या में तैनाती की जाए। जिन रास्तों-चौक चौराहों में प्रदर्शन होना हैं और जूलुस गुजरना है, वहां पर आवश्यकतानुसार मजबूत बैरिकेडिंग की व्यवस्था करें। साथ ही प्रदर्शन के रूट की जानकारी पहले से लेकर शहर की यातायात व्यवस्था के संबंध में योजना बना ले ताकि आमनागरिकों को परेशानियों का सामना कम से कम

करना पड़े। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि इस दौरान राजस्व और पुलिस अधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करें। अधिकारीगण प्रमुख स्थानों पर संयम से कार्य करते हुए सुरक्षाबलों को परिस्थिति अनुसार ही आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दें। उन्होंने टाटीबंध में बन रहे निर्माधीन फ्लाईओवर की भी जानकारी ली और प्रमुख स्थानों पर शाईनबोर्ड लगाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एडीएम, एसडीएम और पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.